



संस्कार उजाला



संस्थापक
श्री आर. के. शर्मा

सच की हुंकार

sanskarujala@gmail.com

संस्थापक स्व० सुखराम शर्मा एवम शिवकुमार शर्मा, श्री प्रकाशवीर

सच की हुंकार

गाजियाबाद से प्रकाशित, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, हापुड, बुलंदशहर, मथुरा आगरा, इटावा, कानपुर एवं लखनऊ से प्रसारित

वर्ष : 12 अंक : 212

शुक्रवार 22 नवंबर 2024, गाजियाबाद

RNI No-UPHIN / 2013 / 50466

पेज : 8 मूल्य : 2 रुपया

राजनाथ सिंह ने विश्व को दिया शांति का संदेश

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गुरुवार को कहा कि विश्व को जारी युद्धों और अंतरराष्ट्रीय क्रम की चुनौतियों के समाधान के लिए बुद्धि के सिद्धांतों को अपनाया चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत ने हमेशा से बातचीत का रास्ता अपनाया है और इसकी वकालत भी करता है। लाओस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और (एडीएमएम प्लस) में चीन के डोंग जून समेत अपने समकक्षों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विश्व का तेजी से विभिन्न क्षेत्रों और खेमों में धुवीकरण हो रहा है। इससे



स्थापित वर्ल्ड आर्डर में तनाव पैदा हो रहा है। दस देशों का आसियान सम्मेलन लाओस की राजधानी वियनतियान में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि हम सभी को भगवान बुद्ध के शांति और सहअस्तित्व के सिद्धांत को और गहराई से अपनाया चाहिए।

राहुल गांधी ने जो बाइडन के यादृशत पर की थी टिप्पणी।

डॉक्टरों के एक संगठन ने पत्र लिखकर सोनिया गांधी से की शिकायत।

नई दिल्ली। मेडिकल प्रैक्टीशनर्स के एक संगठन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की संज्ञानात्मक क्षमताओं (कॉग्नेटिव एबिलिटीज) पर उनकी कथित टिप्पणियों से चिंतित हैं, जो कि उनके मुताबिक काफी असंवेदनशील हैं। 54 वर्षीय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह टिप्पणियां 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अमरावती में एक रैली के दौरान की थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यादृशत की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से की थी। नेशनल मेडिकोज



ऑर्गनाइजेशन (एनएमओ-भारत) के अखिल भारतीय अध्यक्ष सीबी त्रिपाठी ने राहुल गांधी की मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में राहुल गांधी से अपनी टिप्पणियों पर विचार करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियों से उम्र बढ़ने और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के बारे में हानिकारक रुढ़िवादिता को बढ़ावा मिल सकता है। यह टिप्पणी न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए, बल्कि भारत में कई वरिष्ठ

नागरिकों के लिए भी अपमानजनक थी, जो स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस तरह की टिप्पणियां भारतीय मूल्यों के विपरीत हैं, जो बुजुर्गों के सम्मान देने पर जोर देता है। इनका कहना है कि वे टिप्पणियां विपक्ष के नेता की समझ और संवेदनशीलता की कमी को दर्शाती हैं। त्रिपाठी ने सोनिया गांधी को स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों और गलत सूचनाओं के साथ अपने खुद के अनुभवों की याद दिलाई। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें समझना चाहिए कि ऐसी बातें लोगों और समाज के लिए कितनी हानिकारक हो सकती हैं।

दैनिक संस्कार उजाला
बुलंद एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें

संस्कार उजाला समाचार पत्र में रिपोर्टर, खुराचीक, ग्राफिटींग करने वाले लोगों की जरूरत है। तुरंत संपर्क करें।

महेश शर्मा
प्रबंध संपादक
मो.नं.- 9911733939

जन औषधि
रानी दवाईयाँ 15% - 90% तक की बचत कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र
Shop No. 5, House No. 101, Gali No. 3, Village Harola, Sector-5, Opp. Fire Station, Noida, U.P.-201301

FREE HOME DELIVERY Contact No.: 9821725700

सुविचार

सुविचार

अपनी उर्जा को चिता करने में खत्म करने से बेहतर है, इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए।

संक्षिप्त समाचार

आतंकी घुसपैठ का मामला : जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए ने की ताबड़तोड़ छापेमारी

जम्मू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार सुबह जम्मू के कई इलाकों में बड़ी छापेमारी की। यह छापे एक नए दर्जे मामले से संबंधित हैं, जिसमें पाकिस्तान से आतंकीवादियों की घुसपैठ का आरोप लगाया गया है। पिछले दिनों घाटी में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। जिसके बाद आतंकीयों के खिलाफ सुरक्षाबलों का एवम भी तेज हो चुका है। एनआईए की इस कार्रवाई को आतंकीयों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार एनआईए की इस छापेमारी का मकसद पाकिस्तानी आतंकीयों के भारत में घुसने के प्रयासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की मदद से एनआईए के अधिकारी कई स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। इससे पहले, एनआईए ने 5 अक्टूबर को 5 राज्यों के 22 इलाकों पर आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग के शक में साठ साठ छापेमारी की थी। एनआईए की ओर से यह छापेमारी महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुण प्रदेश और दिल्ली में छापेमारी की गई थी। यह कार्रवाई आतंकी संगठन उशा-ए-मोहम्मद से जुड़े मामलों को लेकर की गई थी। एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में बारगुरा और उत्तर क्षेत्रों में भी छापेमारी की थी। बारगुरा में मौलवी इकबाल अहमद के घर पर एनआईए ने सुरक्षा बलों को मदद देती तलाशी ली थी।

मणिपुर में हिंसा रोकने आठ कंपनियों पहुंची, संवेदनशील इलाकों में हंगी तेनाती

इंफाल। मणिपुर में हिंसा के बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 8 कंपनियां इंफाल पहुंच गई हैं। जिन्हें संवेदनशील और सीमांत इलाकों में तैनात किया जाएगा। एक अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि कुश्नार को सीआरपीएफ की 11 कंपनियों का एक और जंथा इस्त्रात पहुंचा। अधिकारी ने कहा कि सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की चार-चार कंपनियों राज्य के संवेदनशील और सीमांत इलाकों में तैनात की जाएगी। सीआरपीएफ की कंपनियों में से एक महिला बटालियन की है। केंद्र में घोषणा की है कि मणिपुर में सीआरपीएफ की 50 नई कंपनियां तैनात की जाएगी। राज्य में हिंसा बढ़ गई है और पिछले सातह पहाड़ी जिले जिराबाम में कांग्रेस और बीजेपी कार्यलयों में तोड़फोड़ भी की गई थी। सुरक्षा बलों ने विगत दिवस मणिपुर के सीएम एन बीरेंद्र सिंह के पैरूक निवास पर हमला करने की आतंकीकारियों की कोशिश को नाकाम कर दिया था। हिंसा तब और भयंकर हो गई जब 11 नवंबर को सुरक्षा बलों और सशस्त्र कुली-जो अत्याचारियों के बीच गोलीबारी के बाद जिराबाम जिले में एक राहत शिविर से मेहती समुदाय की तीन महिलाएं और तीन बच्चे तलाश हुए। इस मुठभेड़ में 10 उखावटी मारे गए थे। पिछले कुछ दिनों में इन छह तलाश लोगों के शव बरामद किए गए हैं। पिछले साल मई से दमनापटी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों और आसपास की पहाड़ियों पर बसे कुली-जो समुदाय के बीच जातीय हिंसा में 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

बिहार के आश्रय गृह में मौत का मामला, एनएचआरसी ने नीतीश सरकार को जारी किया नोटिस

पटना (एजेंसी)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार के पटना के पटेल नगर इलाके में एक आश्रय गृह में खाद्य विषाक्तता की घटना की मीडिया रिपोर्टों के जवाब में स्वतंत्र-संज्ञान शुरू किया है। 7-11 नवंबर, 2024 के बीच हुई इस घटना में मानसिक स्वास्थ्य और बेघर महिलाओं की सुविधा में 13 महिला कैदियों को प्रभावित किया। दुखद रूप से, तीन महिलाओं की जान चली गई, जबकि अन्य में रात का खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त जैसे लक्षण विकसित हुए।



प्रभावित लोगों को जल्द ही इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) में स्थानांतरित कर दिया गया। घटना के मद्देनजर बिहार सरकार के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा वित्त पोषित आवास अब कथित तौर पर जांच के दायरे में है। एनएचआरसी ने इस मामले से उजागर हुए संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि, कानूनी संरक्षक व्यक्तियों या उनके परिवारों को मुआवजा प्रदान किया गया है या नहीं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए

उमर अब्दुल्ला ने किया पूछ का दौरा, कहा- 24 अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों से मैं खुद मिला

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बंगले में पूछ में विकास परियोजनाओं पर 21 सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव के बाद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए आज हम पूछ आए थे। जम्मू में ये पहला जिला है जहां हमने विकास के हवाले से अधिकारियों की बात सुनी है। यहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अफसरों से बातचीत हुई, कुछ मुद्दों के लिए वहां उन्हें जवाबदेह बनाया गया। हमारा फर्ज है कि हम लोगों के साथ तालमेल बनाए रखें। आज लगभग 24 अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों से मैं खुद मिला और यहां जो भी कमियां हैं उसके लिए विदायत दी गई है।



इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनके लिए विशेष रूप से रखी गई बड़ी कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया।

उपाय शामिल होने चाहिए। 14 नवंबर, 2024 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आश्रय गृह के निरीक्षण से पता चला कि कैदी अस्वच्छ परिस्थितियों में रह रहे थे। इसके अलावा, सुविधा में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया रूढ़िवादिता मानकों को बनाए रखने में अपर्याप्त पाई गई, जिसने भोजन विषाक्तता में योगदान दिया हो सकता है।

अब्दुल्ला ने चण्ड स्थित शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूपएसटी) के मुख्य परिसर में चार दिवसीय 'राष्ट्रीय कृषि शिक्षण सम्मेलन एवं किसान मेले' का उद्घाटन किया। मंच पर पहुंचे अब्दुल्ला ने देखा कि उनकी कुर्सी बड़ी थी। उन्होंने एसकेयूपएसटी के प्रबंधन से उनके लिए भी मंच पर बैठे अन्य लोगों जैसी कुर्सी रखने का अनुरोध किया। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जम्मू के प्रति चिंता नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दरबार मूव के महत्व पर भी जोर दिया और उसे एक ऐसी परंपरा बताया जो दोनों क्षेत्रों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देती थी। इसके तहत सरकार श्रीनगर और जम्मू से छह-छह महीने तक काम करती थी।

प्रदूषण का कहर: यूपी, हरियाणा, राजस्थान में सैकड़ों स्कूलों में छुट्टी?

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा अब मानव निर्मित आपदा (प्रदूषण) ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए। यहां पर 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी। इसी तरह यूपी के 6 जिलों में भी वायु प्रदूषण के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ आदि जिलों के 12वीं तक के स्कूल पहले ही बंद करने के आदेश दिए गए थे। अब वायु प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश के हापुड, बुलंदशहर, बागपत आदि जिलों के भी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। यहां भी प्रशासन ने एहतियातन इंटरमीडिएट तक के स्कूल और कॉलेज आगामी आदेश तक बंद रखने को कहा है।

उत्तर प्रदेश के इन जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) काफी बढ़ गया है। गाजियाबाद में एक्यूआई 367, मेरठ का 248, बुलंदशहर का 322, और बागपत का 187 है, जबकि सबसे अधिक एक्यूआई हापुड का है। यहां यह इंडेक्स 519 तक पहुंच गया है, जिसके कारण यहां के स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि जिलों के स्कूल तो पहले ही बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके अलावा भी कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने के आदेश हैं। हरियाणा के रेवाड़ी के जिलाधिकारी अभिषेक मीणा ने प्रदूषण के कारण 12वीं तक की कक्षाएं न लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल 23 नवंबर तक बंद रहेंगे। धिवानी जिले के डीसी महाबोर कौशिक ने 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यहां पर आगामी आदेशों तक स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन

क्लासेज चलाई जाएंगी। चरखी दादरी जिले के स्कूलों को भी बंद रखने के कारण 23 नवंबर तक बंद रखने के निर्देश हैं। जिलाधीश मुनीष शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में पहली बार प्रदूषण के कारण स्कूल बंद रखा गया है। यहां के खैरथल जिले के स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। यहां के कलेक्टर किशोर कुमार ने सभी निजी व सरकारी स्कूलों के अवकाश की घोषणा की है। यह आदेश पांचवीं तक के स्कूलों के लिए जारी किया गया है, जो आगामी आदेश तक लागू रहेगा। राजस्थान के भी कई जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बढ़ा हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान के लगभग 25 जिलों का एक्यूआई लेवल मंगलवार को औसतन 200 है।



राहुल बोले- PM मोदी अडाणी को बचा रहे

नई दिल्ली। भाजपा ने गुरुवार को कहा अडाणी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी केस में नामित चारों राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और तमिलनाडु में उसकी सहयोगी पार्टी की सरकार थी। पार्टी प्रवक्ता संवित पात्रा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने 2019 में राफेल मुद्दा उठाया था, लेकिन मांग में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। दरअसल, गुरुवार को ही राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडाणी पर लगे करपशन के आरोपों पर प्रेस कांफ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि अडाणी जी 2 हजार करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं,



क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडाणी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा है। अडाणी की प्रोटेक्टर एडवोकेट की चैवरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर

योजना बना रहे हैं। आरोप है कि ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर राज्य में बिजली कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी लोग बंधुत खुश हुए थे। उसी दिन झारखंड से 'पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा-अभियान' यानी पीएम-जनमन की शुरुआत की गई थी। संविधान की आठवीं अनुसूची में 'संथाली' को शामिल करने पर राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आदिवासी भाषा 'संथाली' को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयासों में मैंने भी योगदान दिया है। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में संभव हुआ।

स्टालिन ने जयशंकर को पत्र लिख रिहाई का किया आग्रह

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को पत्र लिख केंद्र की सहायता मांगी है। स्टालिन ने कहा कि इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी नौसेना ने 14 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया था और अब उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। मछुआरों को जल्द रिहाई का आग्रह दरअसल, हिरासत में लिए गए मछुआरों में सात तमिलनाडु के हैं। मछुआरों को 3 जनवरी 2024 को गुजरात के पोर्बंदर से मछली पकड़ने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी पाकिस्तानी नौसेना ने जब्त कर लिया। अपने पत्र में स्टालिन ने लगभग 10 महीने की हिरासत पर चिंता व्यक्त की और गिरफ्तार मछुआरों के परिवारों पर



पड़ने वाले भावनात्मक और वित्तीय तनाव के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कमाने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति ने उनके परिवारों को गंभीर संकट में डाल दिया है। स्टालिन ने लिखा, हरलंबे समय तक हिरासत में रखे जाने और इसमें शामिल मानवीय चिंताओं को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी मछुआरों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस मामले को ठोस और सार्थक तरीके से उठाया

जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्र से जब्त मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया, जो मछुआरों और उनके परिवारों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हाल ही में स्टालिन ने जयशंकर से श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों की बढ़ती गिरफ्तारों के मामलों पर तत्काल कूटनीतिक उपाय करने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि वर्ष 2024 में सात वर्षों में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की सबसे अधिक गिरफ्तारी हुई है। तमिलनाडु सरकार ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है, राज्य के मछुआरा समुदाय की सुरक्षा की वकालत की है, जिनके सदस्य अक्सर आजीविका की तलाश में विवादित जल में जाते हैं।

सुलगते-दहकते मणिपुर का जिम्मेदार कौन?



ताजा जानकारी के अनुसार हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा जिरिबाम में एक महिला की हत्या की गई। इस संबंध में 8 नवंबर को जिरिबाम स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सशस्त्र उग्रवादियों ने जिरिबाम के जाकुरधोर करोंग और बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन पर मौजूद सीआरपीएफ चौकी पर हमला किया। इस सिलसिले में 11 नवंबर को बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। बोरोबेकरा में घर्षों को जलाने और नागरिकों की हत्या का मामला सामने आया। इस संबंध में 11 नवंबर को बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। 11 नवंबर को, मणिपुर पुलिस ने कहा कि बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन और जिरिबाम के जकुरधोर में सीआरपीएफ कैम्प पर छद्म वदी पहने और अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में 10 सशस्त्र उग्रवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार, कुछ घंटों बाद सशस्त्र उग्रवादियों ने उसी जिले से महिलाओं और बच्चों सहित छह नागरिकों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि मणिपुर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को राज्य में व्यवस्था

और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। पिछले साल मई से जातीय संघर्ष से जूझ रहे मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने के बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा के कारण स्थिति अस्थिर हो गई है। गुस्ताई भीड़ में इफाल चाटी के विभिन्न जिलों में तीन भाजपा विधायकों और एक कांग्रेस विधायक के घर्षों में आग लगा दी जबकि सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री एन बीरन सिंह के पैतृक आवास पर धावा बोलने की प्रदर्शनकारियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। मणिपुर में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने सीएपीएफ की 50 अथक कंपनियों भेजने का फैसला किया है। इस तरह अब राज्य में सीएपीएफ की 268 कंपनियां तैनात हो जाएंगी। इनमें पांच हजार जवानों की संख्या और बढ़ जाएगी। इस तरह, राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती की संख्या 26,800 हो जाएगी। इन 50 कंपनियों में सबसे बड़ी संख्या सीआरपीएफ की कंपनियों की होगी, जबकि बाकी कंपनियां बीएसएफ और अन्य सुरक्षाबलों की होंगी। जो अतिरिक्त 50 कंपनी यहां जाएंगी उनमें अतिरिक्त 6500

अर्धसैनिक बल होंगे। यहां पहले से ही 40,000 केंद्रीय बल मौजूद हैं। इसी बीच एक शरणार्थी कैम्प में से कुछ व्यक्तियों के अपहरण और हत्या के बाद हिंसा के हालात और भी तेज हो गये। यहां तक कि दोनों समुदायों ने चर्चों और मॉर्चों में भी तोड़ फोड़ की और उनको आग भी लगाई। मणिपुर में सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। इस घटनाक्रम की कुछ हेरान करने वाली बातें हैं। जब ये दंगे भड़के थे तथा ऐसा गृह-युद्ध शुरू हुआ था तो इन्हें न सम्भाल सकने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह पर डाली गई थी। तब ये समाचार भी आने लगे थे कि स्थिति को अच्छी तरह न सम्भाल सकने तथा इस सीमा तक बिगड़ने देने के कारण मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया जाएगा, परन्तु अब वहां खतरनाक हालात पैदा हो जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जाना बड़ी हैरानी की बात यह है। अब जब यह हिंसा खत्म नहीं हो रही तो लोगों ने गुस्से में भाजपा विधायकों, मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री तक के घर्षों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने वहां के कांग्रेस नेताओं को भी नहीं बखशा। बात अकेले मणिपुर की नहीं है, बात देश के इस पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की है, जहां पहले ही लगातार गड़बड़ होने के समाचार मिलते रहे हैं। लोग बड़े स्तर पर बंदे हुए दिखाई देते हैं, यहां की निरंतर बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए कोई बड़े यत्न नहीं किए गए। मणिपुर एक छोटा राज्य है, परन्तु इसकी अशांति स्थिति का प्रभाव समूचे देश पर पड़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक तौर पर मणिपुर में भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इससे नाता तोड़ने की घोषणा कर दी है। कुकी समुदाय के भी 7 विधायक भाजपा से संबंधित हैं, परन्तु इसके बावजूद अभी वहां की सरकार के टूटने का कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा, परन्तु सरकार टूटने से भी बड़ा मामला धार्डिचारा बनाए रखने और शांति स्थापित करने का है, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में समूचे देश पर पड़ेगा। माहौल को सम्भालने तथा एकपुरु करने की जिम्मेदारी इस समय भाजपा और केंद्र सरकार को है। विशेष रूप से सरकार को मणिपुर संबंधी अपनी नीतियों पर पुनः सोचने तथा हालात को सुधारने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत होगी।

मनोज कुमार अग्रवाल

अब जब यह हिंसा खत्म नहीं हो रही तो लोगों ने गुस्से में भाजपा विधायकों, मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री तक के घर्षों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने वहां के कांग्रेस नेताओं को भी नहीं बखशा। बात अकेले मणिपुर की नहीं है, बात देश के इस पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की है, जहां पहले ही लगातार गड़बड़ होने के समाचार मिलते रहते हैं। लोग बड़े स्तर पर बंदे हुए दिखाई देते हैं, यहां की निरंतर बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए कोई बड़े यत्न नहीं किए गए।

संपादकीय

भारत के सिद्धांतों का विस्तार

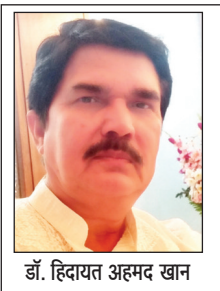
ब्राजील के रिचो द जेनेरियो में हुए जी-20 के दो दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन को लेकर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने बहुत सी उम्मीदें संजोई थीं, लेकिन दुनिया के सामने मौजूद समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में सम्मेलन को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। यूक्रेन संघर्ष और गाजा त्रासदी पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ जिसमें युद्धरत गाजा के लिए अधिक सहायता और पश्चिम एशिया एवं यूक्रेन में शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया गया है। आशा बंधी थी कि दुनिया के नेता कूटनीति और वार्ता के जरिए गाजा और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की दिशा में सफल होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि पिछले दो वर्षों के दौरान परस्पर विरोधी मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि बीच का कोई रास्ता खोजने की संभावना बहुत कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का जी-20 का आदर्श वाक्य (थीम) 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' उतना ही प्रासंगिक है, जितना पिछले साल था।

लेकिन हकीकत यह है कि धरती बंदी है, परिवार में कलह है, और महत्वाकांक्षा के कारण समान भविष्य को नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान के सबसे ज्वलंत मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वैश्विक संघर्षों के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से रोलबल साउथ के विकासशील और अर्धविकसित देश सबसे अधिक प्रभावित हैं। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के नेता युद्ध रोकने की बजाय हथियारों की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन संघर्ष को रोकने के पक्ष में हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में इस्राइल को अधिक समर्थन देने तथा चीन के खिलाफ सख्त आर्थिक और सैनिक रवैया अपनाने के समर्थक हैं। ऐसे में संयुक्त वक्तव्य में युद्धसमाप्त करने का आह्वान मात्र औपचारिकता है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वेरा ने भूख और गरीबी से लड़ने के अभियान का आह्वान किया। इस अभियान को पहले ही करीब 80 देशों का समर्थन हासिल हो चुका है। जाहिर है कि सम्मेलन की यह एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इस अभियान का बीज भारत ने पिछले साल जी-20 की अध्यक्षता करते हुए रोपा था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा के लिए अपनाए गए सिद्धांतों का विस्तार बताया।

चिंतन-मनन

उपाय भी ठीक हो

उपाय सम्यक् होना चाहिए। उपाय का बड़ा महत्व होता है। जहां समस्या आती है, आदमी उपाय खोजता है। समाधान तब तक नहीं होता, जब तक उपाय नहीं मिल जाए। उपाय स्वयं भी खोजा जा सकता है और उपाय खोजने के लिए गुरु की शरण या उस विषय को जानने वाले व्यक्ति की शरण भी ली जा सकती है। कोई संन्यासी था। भीड़ बहुत होती। सभी संन्यासी अपरिग्रही नहीं होते। कुछ संन्यासी बहुत परिग्रह भी रखते हैं। यह अपनी-अपनी परम्परा है। बड़ा आश्रम था। बहुत धन और बहुत लोगों की भीड़। वह परेशान हो गया। गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव! और तो सब ठीक है, पर एक बड़ी समस्या है। भीड़ बहुत हो जाती है, इतने लोग आते हैं कि मैं अपनी साधना पूरी तरह नहीं कर पाता, समय नहीं मिलता। रात-दिन चर-सा चलता है। गुरु ने कहा, तुम एक काम करो, गरीब लोग आए तो उनको कर्ज देना शुरू कर दो और जो धनवान लोग आए। तो उनसे मांगना शुरू कर दो। उपाय हाथ में लग गया। उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया-जो निर्धन आते, उन्हें कर्ज देना शुरू किया और धनी आते उनसे धन मांगना शुरू किया। पांच-दस दिन में भीड़ बिल्कुल छंट गई। क्योंकि जिन्होंने कर्ज लिया वे वापस किसलिए आते? सामने आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वापस तो देना नहीं था- धनियों से मांगना शुरू किया तो उन लोगों ने सोचा कि अब तो जाना ठीक नहीं है। जाते ही पहले यह होगा कि लाओ-लाओ। भीड़ कम हो गई। उपाय ठीक मिलता है तो दोनों बातें हो जाती हैं। हमारे हाथ उपाय लगना चाहिए।



डॉ. दिदायत अहमद खान

ए क तरफ विश्वगुरु बनने की दहलीज पर खड़े भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना में सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अडानी मामले ने देश की नाक कटाने जैसा संदेश दे दिया है। इसकी जांच और हकीकत जल्द से जल्द सामने आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में देशवासियों के विश्वास का मामला भी जुड़ता है। दरअसल भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्तखोरी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिका की कोर्ट ने इस मामले में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष पीएम मोदी पर सीधे हमलावर है। इस मामले में गौतम अडानी और सात अन्य लोगों पर अरबों डॉलर की रिश्तखोरी और धोखाधड़ी की लेकर अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई हुई है। खास बात यह है कि मामला जैसे ही उजागर हुआ अडानी समूह ने अमेरिका में 600 मिलियन डॉलर का बॉन्ड रद्द कर दिया। इस मामले का आरोप भारत के शेयर बाजार में गुरुवार को मिला, जबकि मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई। यही नहीं अमेरिकी अदालत की तरफ से रिश्तखोरी के आरोपों के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने भी अडानी समूह की



अशोक भाटिया, मुख्यई

बाद तमाम न्यूज चैनलों और चुनाव सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल नतीजे में आसानी से भाजपा की सरकार बनती दिखावा था। चार प्रमुख एग्जिट पोल में समाधारी भाजपा को एकतरफा 70 से ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाया गया था। वहीं एक चैनल ने भाजपा को 50 से 65 के बीच सीटें दी थीं। हरियाणा 2024 विधानसभा चुनाव की बात करते तो एग्जिट पोल के नतीजे इस प्रकार थे, इंडिया टुडे-सी वोट: कांग्रेस को 50 से 58 सीटें और बीजेपी को 20 से 28 सीटें,एक्सप्रेस माई-इंडिया: कांग्रेस को 53 से 65 सीटें और बीजेपी को 18 से 28 सीटें,भास्कर रिपोर्टरस पोल: कांग्रेस को 44 से 54 और बीजेपी को 19 से 29 सीटें,रिपब्लिक मिडिया: कांग्रेस को 55 से 62 और बीजेपी को 18 से 24 सीटें, ये कुछ एग्जिट पोल हैं जिनमें हरियाणा में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने की बात कही गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो इनके ठीक उलट हुआ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने रूप पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया और बीजेपी में जीत की हंटिक लगाई। नतीजों में बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। इन चुनाव नतीजों ने एक बार फिर एग्जिट पोल और उनको करने वाली एजेंसियों की विश्वसनीयता को सवालियों के घेर में ला दिया है,हालांकि जम्मू-कश्मीर के नतीजे एग्जिट पोल के इर्द-गिर्द रहे, यहां नेशनल लोकसभ-कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है, 2014 में जम्मू-कश्मीर राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। तब 87 सीटों वाली विधानसभा के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2014 तक पांच चरणों में मतदान हुआ था। 2014 के एग्जिट पोल में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने का अनुमान जताया गया था। जम्मू कश्मीर में सत्ता में किसकी वापसी होगी, इसका अनुमान स्पष्ट नहीं था। हालांकि, उस वक 87 सीटों वाले जम्मू-कश्मीर में पीडीपी

और बीजेपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई थी। इन एग्जिट पोल में बताया गया था कि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनती सकती है, जबकि भाजपा दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर आ सकती है। वहीं एग्जिट पोल में जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व की नेशनल काँग्रेस सरकार को बड़ी हार का सामना करने हुए दिखाया गया था। जब नतीजे आए तो तमाम एग्जिट पोल काफी हद तक गलत साबित हुए। जहां अनुमानों में सत्तधारी भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती दिखाई गई थी। वहीं, नतीजों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सत्तधारी भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटों पर जीत जरूरी थी। भाजपा को सबसे ज्यादा 40 सीटें मिलीं। कांग्रेस 31 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। विधानसभा चुनाव में जनपा 10 सीटें जीतने में सफल रही। सात निर्दलीय, इंडियन नेशनल लोकसभ (इनेलो) एक और हरियाणा लोकसभ पार्टी को एक सीट पर जीत मिली। चुनाव के बाद 10 सीटों वाली जनपा के साथ पार्टी ने गठबंधन किया और राज्य की सत्ता में वापसी की। 27 अक्टूबर 2019 को मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। किंग मेकर बने स्वयं चोटाला ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मनोहर लाल की जगह नयल सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश में 2014 के एग्जिट पोल का काफी हद तक सही साबित हुए थे। 2014 में जम्मू-कश्मीर राज्य में चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव के परिणाम 23 दिसंबर 2014 को घोषित किये गये थे। 87 सदस्यीय विधानसभा में महबूबा मुन्नी की जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिलीं। वहीं, दूसरे स्थान पर भाजपा थी जो 25 सीटों पर जीतने में

सफल रही। फारुख अब्दुल्ला की नेशनल काँग्रेस को 15 जबकि कांग्रेस को 12 सीटें पर जीत मिली। तीन सीटें पर निर्दलीय तो चार सीटें पर अन्य छोटे दलों को जीत मिली। नतीजों से साफ था कि कोई भी दल बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। नतीजों के करीब छह महीने बाद पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पीडीपी को 25 सदस्यों वाली भाजपा का समर्थन था। इस तरह इस गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को जुटा लिया। 7 जनवरी 2016 को सईद के निधन के बाद राज्य में एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चिता का दौर आया। राज्य में राजवल्लभ का शसन लगाया गया। कब्रि लाल ने नतीजों की अनिश्चितता के बाद भाजपा और पीडीपी में फिर से समझौता हुआ और महबूबा मुन्नी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 4 अप्रैल 2016 को महबूबा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। पीडीपी-भाजपा की यह गठबंधन सरकार दो साल से ज्यादा तक चलती। जून 2018 में भाजपा ने महबूबा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके साथ ही सईद प्रकर पूरी तरह फेल साबित होते हैं? दरअसल एग्जिट पोल वास्तव में कुछ और भी बालिक चोटार का केवल रूझान ही होता है, जिसके जरिये अनुमान लगाया जाता है कि नतीजों का शुद्धांक किस ओर हो सकता है। एग्जिट पोल के दावों का ज्यादा वैज्ञानिक आधार इसलिए भी नहीं माना जाता क्योंकि ये कुछ थोड़ा कुछ इजाजत इजाजत लोगों से बातचीत करके उसी के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं और प्रायः इमीलिए इन्हें हकीकत से दूर

माना जाता रहा है। एग्जिट पोल में प्रायः मीडिया से आ रही खबरों, चुनाव का इतिहास और हवा के रुक का वायुमंडल भी शामिल रहता है। जब कोई मतदाता अपना मत देकर मतदान केन्द्र से बाहर निकलता है तो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां उससे उसका रूझान पूछ लेती हैं। अधिकतर एग्जिट पोल परिणामों को प्रायः यह समझ लिया जाता है कि ये पूरी तरह सही ही नहीं किये जाते हैं। समझकर पोल प्रायः यह भूल जाते हैं कि ये केवल अनुमानित आंकड़े ही होते हैं और कोई जरूरी नहीं कि मतदाता ने सर्वे करने वालों को सच्चाई ही बताई हो। दरअसल सर्वे के दौरान मतदाता बहुत बाने इस बात का सही जवाब नहीं देते कि उन्होंने अपना वोट किस पार्टी या प्रत्याशी को दिया है। देश में चुनाव प्रायः विकास के नाम पर या फिर जाति-धर्म के आधार पर ही लड़े जाते हैं और यदि बात विधानसभा चुनावों की हो तो चुनाव में बहुत से स्थानीय मुद्दे भी हावी रहते हैं, ऐसे में यह पता लगा पाना इतना आसान नहीं होता कि मतदाता ने अपना वोट किसके दिया है। नित्यचार में अधिकांश लोग एग्जिट पोल को एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण नहीं करके वोट के फैसले को निरस्त कर दिया। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी और इस मांग के जोर पकड़ने पर तब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में संशोधन के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करते हुए सुनिश्चित किया गया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता, तब तक किसी भी रूप में एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता। अशोक भाटिया, चर्चित स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार लेखक 5, दरभंगा से लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता में चरई मौल्य अवार्ड से सम्मानित।

इसी आधार पर ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया जाता है कि जनता किस पार्टी या किस प्रत्याशी का चुनाव करने जा रही है। ओपिनियन पोल को ही झूठी-पोल्ड भी कहा जाता है। पोल्ट पोल प्रायः मतदान की पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने के अगले दिन या फिर एक-दो दिन बाद ही होते हैं, जिनके जरिये मतदाताओं की ही जनता के प्रयास किए जाते हैं कि ये पूरी तरह सही ही नहीं किये जाते हैं। और अक्सर माना जाता रहा है कि पोल्ट पोल के परिणाम एग्जिट पोल के परिणामों से ज्यादा सटीक होते हैं। 1998 में चुनाव पूर्व सर्वे अधिकांश टीवी चैनलों पर प्रसारित किए गए और तब ये बहुत लोकप्रिय हुए थे लेकिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर 1999 में चुनाव आयोग द्वारा ओपिनियन पोल तथा एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी और इस मांग के जोर पकड़ने पर तब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में संशोधन के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करते हुए सुनिश्चित किया गया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता, तब तक किसी भी रूप में एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता। अशोक भाटिया, चर्चित स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार लेखक 5, दरभंगा से लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता में चरई मौल्य अवार्ड से सम्मानित।

वर्षई पूर्व - 401208 (मुंबई) E-MAIL - vsaai@rediffmail.com केवल

वार्डर पत्रक 922 1232 1310

साबरमती रिपोर्ट पर सीएम योगी का पहला रिएक्शन

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक सत्य को देशवासियों के सामने लाने का बड़ा और सफल प्रयास किया गया है। साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम व कलाकारों ने गोधरा के सच को सामने लाकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा किया है। फिल्म यह बताती है कि किन लोगों ने कैसे षड्यंत्र किया ऐसे लोगों को देश के सामने लाया ही जाना चाहिए।

जनता के साथ फिल्म देखने के बाद पत्रकारों से कहा कि साबरमती ट्रेन में सवार श्रद्धालु अयोध्या से धार्मिक अनुष्ठान करके लौट रहे थे, गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर उनके साथ जो हुआ उस पर पर्दा डाला जाता रहा। षड्यंत्र करने वाले अलग-अलग स्तरों पर सच्चाई को छिपाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आज भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसे लोग देश, समाज व लोगों के हितकारी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ये



फिल्म ऐसे समय आई है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भव्य भगवान श्रीराम का मंदिर बना है, फिल्म की मूल घटना अयोध्या से जुड़ी है, गोधरा के सत्य को सभी जान सकें, इसे अधिक

अवस्थी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने कहा कि मैं रूढ़ साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस वास्तविक सच को देश की जनता के सामने फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी को रूढ़ साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखनी चाहिए और गोधरा का सच के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। साबरमती

रिपोर्ट की अभिनेत्री राशि खन्ना ने कहा कि गुजरात दंगों को सब जानते हैं लेकिन, गोधरा की सच्चाई से युवा व आम लोग परिचित नहीं हैं, यह भी स्वीकारा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़कर जाना कि वहाँ क्या हुआ? अब चाहते हैं कि सब जाने कि गोधरा में 69 श्रद्धालु कैसे मारे गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फिल्म के लिए ट्वीट करने व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी में टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद दिया।

भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश नागर के नेतृत्व में ग्राम रघुनाथपुर में सनसिटी बिल्डर से प्रभावित गांवों के किसानों की मीटिंग हुई।

संस्कार उजाला

गाजियाबाद आज दिनांक 21/11/2024 को भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश नागर के नेतृत्व में ग्राम रघुनाथपुर में सनसिटी बिल्डर से प्रभावित गांवों के किसानों की मीटिंग हुई। लोकेश नागर ने बताया कि सनसिटी बिल्डर ने 20 साल से किसानों की जमीन को बंधक बना रखा है। उस जमीन पर भी काम नहीं करने दे रहा है जो सनसिटी बिल्डर के डी पी आर में भी नहीं है। जो जमीन बिल्डर के कब्जे में है उस भी निर्माण कार्य नहीं कर रहा है, साथ ही उन खरीदारों को



भी परेशान कर रहा है जिन्होंने 20 साल पहले प्लॉट लिए थे। आज उन खरीदारों को परेशान कर बिल्डर की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने पैसे ले लो जो उस समय आपने दिए थे। किसानों के साथ भी यही हो रहा है कि अपनी जमीन पर खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्डर द्वारा किसानों एवम

खरीदारों का बहुत शोषण हो लिया। अब भारतीय किसान संगठन बिल्डर को आईना दिखाने का काम करेगा। बहुत जल्द बड़े आंदोलन का आगाज होगा। इस मौके पर टेकराम नागर, अलबेला यादव, दिनेश यादव, धर्मवीर प्रधान, महेन्द्र प्रधान, अमोल, विनोद यादव, आदि किसान मौजूद रहे।

कार्तिक पूर्णिमा मेला गढ़मुक्तेश्वर सकुशल संपन्न होने के उपरांत, साफ सफाई का विशेष अभियान चलाकर संपूर्ण मेले की कराई गई सफाई : सीडीओ

कार्तिक पूर्णिमा मेले स्थल का युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर संपूर्ण घाटो को बनाया स्वच्छ, मेले स्थल का मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया गया औचक निरीक्षण



उजाला

जिला प्रभारी अमित शर्मा हापुड़। जिलाअधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा के कुशल निदेशन में गढ़ गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेला 2024 को सकुशल संपन्न कराये जाने

के पश्चात दिनांक 16 नवंबर 2024 से दिनांक 21 नवंबर 2024 तक वृहद स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाकर संपूर्ण मेले की सफाई करवाई गई। मेले स्थल पर साफ सफाई की

व्यवस्था को देखने हेतु मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम द्वारा किया गया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आरती मिश्रा एवं कार्यालय जिला पंचायत के अधिकारी/

हापुड़ रेलवे स्टेशन पर गंदगी की दुर्गंध संक्रमित बीमारियों को दे रही न्यौता

संस्कार उजाला

हापुड़/ हापुड़ रेलवे स्टेशन का भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के द्वारा सौंदर्य करण के शिलान्यास के बावजूद भी पांचों प्लेटफार्म पर गंदगी की दुर्गंध संक्रमित बीमारियों को न्यौता दे रही है। सफाई कर्मियों का वेतन नहीं मिलने को लेकर सफाई कर्मियों के द्वारा हड़ताल की हुई है। आपको बता दें कि हापुड़ रेलवे स्टेशन की साफ सफाई का जिम्मा एक दिल्ली के प्राइवेट फर्म को दिया हुआ है। जिसमें लगभग 22 सफाई कर्मियों पर रेलवे स्टेशन की सफाई का जिम्मा है। उसके बावजूद भी हापुड़ रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैली हुई है टॉयलेट गंदे हैं प्लेटफार्म पर कर और पांच पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मीना से साफ सफाई नहीं हुई है जिसकी शिकायत यात्रियों के द्वारा रेल मंत्री से भी की जा चुकी है। वहीं रेलवे के आला अधिकारी का कहना है कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई है जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाएगा।



और वहीं ब्रजनाथ पुर शूगर मिल पर करीब 53 करोड़ रुपए किसानों का बकाया गन्ना भुगतान है जिसके लिए भी जल्द रणनीति बनाई जाएगी। और खाद व डीएपी की समस्या लगातार चल रही जिसका जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। क्या कहिन जिला गन्ना अधिकारी सना आफरीन जिला गन्ना अधिकारी

भारतीय किसान यूनियन (टिकैट) की आयोजित मासिक पंचायत में 26 नवंबर को प्रदेश स्तरीय जिला कलेक्टर का घेराव करने को लेकर रूपरेखा की तैयार की गई

संस्कार उजाला

हापुड़/ भारतीय किसान यूनियन (टिकैट) के मुख्य जिला कार्यालय पर मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। जिसका संचालन धौलाना तहसील अध्यक्ष रविन्द्र सिंह और अध्यक्षता रामबीर सिंह द्वारा की गई। मासिक पंचायत के दौरान किसान और मजदूरों की समस्याए रखी गईं। साथ ही आयोजित पंचायत में जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैट और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय 26 नवंबर को जिला कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सिंभावली शूगर मिल पर करीब एक सौ छ करोड़



सना आफरीन का कहना है कि किसानों के बकाया गन्ना भुगतान सिंभावली शूगर मिल और वह ब्रजनाथपुर शूगर मिल पर करीब 159 करोड़ रुपए बकाया है। जिसमें धीरे धीरे बकाया गन्ना भुगतान चल रहा है। और आज भी हमने करीब धौलाना सोसायटी के करीब फान्लड की तरफ जा रहा है। वहीं हमारा लगातार प्रयास है कि जल्द से जल्द गन्ना भुगतान बढ़ाकर कमलोट किया जाए। इस मौके पर महिला विंग जिला अध्यक्ष नीलम त्यागी, जिला उपाध्यक्ष पूनम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कल्पना देवी, जिला महासचिव रमा शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सरिता देवी, जिला

उपाध्यक्ष शोभा देवी, जिला सचिव राजवीरी देवी, जिला प्रवक्ता कुंवर खुशनुद, मेरठ मंडल संगठन मंत्री महिपाल सिंह उर्फ गुजराल, जिला मीडिया प्रभारी अमजद खान, जिला संरक्षक पीके वर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष नौशाद अली, जिला कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर, धौलाना ब्लॉक अध्यक्ष उमेश शर्मा, बाबूगढ़ नगर अध्यक्ष शोखर चौधरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सिंह, नीरज शर्मा, संगठन मंत्री पालू राम, नरेंद्र त्यागी ओमेश बना तहसील संयोजक विनोद शर्मा, संजीव कुमार, सुशील कुमार, पवन त्यागी, जयराम सिंह, रामवीर सिंह समेत मौजूद रहे।

प्रचार-प्रसार करने हेतु जन मानस तक जानकारी पहुंचाने के लिए छोटे-छोटे वीडियो क्लिप बनाकर उसे प्रकृत चित्रण केन्द्र में चलाया जाये, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग फासिल्स पार्क के इतिहास को जान सकें और उसे देखने हेतु जनपद में आएं। इस दौरान मंत्रीगण ने देखों अपना देश, उत्तर प्रदेश के आकर्षण पर्यटक स्थल को दें वोट, उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस को सुधारने का सुल्हाय मौका अभियान के अन्तर्गत सैल्फी ली लियें। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहें।

प्रभारी मंत्री व वन मंत्री ने सलखन फासिल्स पार्क का किये निरीक्षण।

संस्कार उजाला

व्यरो चीफ सोनभद्र अरविन्द गुप्ता। सोनभद्र। रवीन्द्र जायसवाल राज्यमंत्री/जनपद के प्रभारी मंत्री/स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं पंजीयन, डॉ0 अरूण कुमार राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण एवं जन्तु उद्यान ने सलखन फासिल्स पार्क का निरीक्षण किये, निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि सलखन फासिल्स को बेहतर ढंग से विकसित किया जाये, जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बनें, इसके लिए बेहतर ढंग से कार्ययोजना बनायी जाये, इस दौरान डॉ0 अरूण कुमार



राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण एवं जन्तु उद्यान ने उपस्थित अधिकारियों के निर्देशित करते हुए कहा कि सलखन फासिल्स पार्क को विकसित करने हेतु इस प्रकार की कार्ययोजना बनायी जाये कि सलखन फासिल्स पार्क की पहचान राष्ट्रीय स्तर के पार्क के रूप में हो, इस दौरान

मंत्रीगण ने सलखन फासिल्स पार्क के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में डी0एफ0ओ से जानकारी प्राप्त की, तो जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह व डी0एफ0ओ कैमूर द्वारा बताया गया, कि फासिल्स पार्क के सौन्दरीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा डेढ़ करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गयी है, जिसके माध्यम से पर्यटकों के बैठने हेतु दो ग्लोवर, नेचर ट्रेलर, प्रकृत चित्रण केन्द्र, सुरक्षा व्यवस्था के आवश्यक प्रबन्ध, गेट का निर्माण आदि कार्य कराये जायें, प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि सलखन फासिल्स पार्क के महत्वपूर्ण

प्रचार-प्रसार करने हेतु जन मानस तक जानकारी पहुंचाने के लिए छोटे-छोटे वीडियो क्लिप बनाकर उसे प्रकृत चित्रण केन्द्र में चलाया जाये, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग फासिल्स पार्क के इतिहास को जान सकें और उसे देखने हेतु जनपद में आएं। इस दौरान मंत्रीगण ने देखों अपना देश, उत्तर प्रदेश के आकर्षण पर्यटक स्थल को दें वोट, उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस को सुधारने का सुल्हाय मौका अभियान के अन्तर्गत सैल्फी ली लियें। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहें।

एसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा नवंबर माह 2024 के तहत वाहन चालकों का कराया नेत्र परीक्षण



संस्कार उजाला

हापुड़/एसपी कुंवर ज्ञानेंजय सिंह के कुशल निर्देशन में सड़क सुरक्षा नवंबर माह 2024 के अंतर्गत यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण कराया गया। और साथ ही सर्दी के मौसम में बढ़ते कोहरे और धुंध के मद्देनजर वाहनों पर रेडियम स्टीकर लगाकर चलने के साथ सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, से संबंधित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई।

राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण एवं जन्तु उद्यान ने उपस्थित अधिकारियों के निर्देशित करते हुए कहा कि सलखन फासिल्स पार्क को विकसित करने हेतु इस प्रकार की कार्ययोजना बनायी जाये कि सलखन फासिल्स पार्क की पहचान राष्ट्रीय स्तर के पार्क के रूप में हो, इस दौरान

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई चकबंदी विभाग की समीक्षा

चकबंदी अधिकारी को दिए निर्देश, गांव में की जा रही चकबंदी का बनाएं मैप : डीएम

संस्कार उजाला

हापुड़। आज कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा की अध्यक्षता में चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में चकबंदी विभाग में कार्यरत बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी / चकबंदी अधिकारी / सहायक चकबंदी अधिकारीगण उपस्थित रहे है। जनपद हापुड में कुल 21 ग्राम चकबंदी प्रक्रियाधीन है, जिसमें से जनपद हापुड में 13



ग्राम तहसील- गढ़मुक्तेश्वर के नवप्रसारित तथा इसके अतिरिक्त 01 ग्राम पूर्व से चकबंदी प्रक्रियाओं में प्रचलित है तथा तहसील हापुड के 06 ग्राम तथा

तहसील-धौलाना का 01 ग्राम चकबंदी प्रक्रियाओं में प्रचलित है। उक्त ग्रामों में जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबंदी महोदया हापुड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की चकबंदी निदेशालय स्तर से जारी कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रगति बढ़ाने तथा चकबंदी न्यायालयों में 03 वर्षों से अधिक पुराने वादों वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु व शासन / चकबंदी निदेशालय / जिला स्तर पर प्राप्त परिवार/ आई०जी०आर०एस० के गुणवत्ता पूर्ण ससमय निस्तारण के निर्देश भी दिये गये है।

सीतापुर: हल्दी के दिन दूल्हा-दुल्हन की मौत

लड़की के घर में फंदे से लटके मिले शव, परिजनों का आरोप- जीजा ने मारकर लटकाया



सीतापुर। हल्दी की रस्म के बीच दूल्हा-दुल्हन ने जान दे दी। लड़की के घर में दोनों का शव फंदे पर लटका मिला। 25 नवंबर को दोनों की शादी थी। शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा रखा था। घटना गुरुवार दोपहर सीतापुर के महामुदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मिठौरा गांव की है। दूल्हे के मामा सुनील ने बताया- गुरुवार रात लड़की के घर गया था। गुरुवार

सुबह घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। खुशी में परिजन नाच-गा रहे थे। इसी दौरान परिजनों ने देखा कि रूचि के कमरे में उसका और गुरुवार का शव चादर के फंदे के सहारे लटक रहा है। दोनों के पैर जमीन को छू रहे थे। शव की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लड़के के परिजनों ने लड़की के जीजा पर हत्या करके लटकाने का आरोप लगाया है। एसपी साउथ प्रवीण रंजन सिंह ने बताया-



पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है। बरगदिया गांव के गुरुडू (25) का मिठौरा गांव की रूचि (18) से 3 साल से प्रेम संबंध था। दोनों परिवार के लोग रिश्ते के लिए राजी थे। गुरुडू का आप दिन रूचि के घर आना जाना था। गुरुडू मजदूरी करता था। मामा सुनील ने बताया- दोनों परिवारों की रजामंदी से गुरुडू और रूचि की

सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 24 नवंबर को शादी होने वाली थी। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लेकिन, किसी कारणवश प्रशासन ने विवाह योजना की डेट आगे बढ़ा दी। इसके बाद परिजनों ने 25 नवंबर को गांव के ही मंदिर में शादी करने का निर्णय लिया। सुनील ने बताया- दोनों परिवारों में शादी की रस्म शुरू हो गई थी। गुरुवार को दोनों की हल्दी होनी थी। दोनों परिवारों में तय



हुआ था कि लड़की के घर पर ही हल्दी की रस्म होगी। इसके लिए गुरुडू बुधवार रात को ही रूचि के घर पहुंच गया था। गुरुवार सुबह हल्दी की रस्म के बीच दोनों का शव एक ही कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने बताया कि घटना से दो-तीन दिन पहले रूचि के जीजा से गुरुडू का विवाद हुआ था। दरअसल, वह इस शादी के खिलाफ था। लड़के के परिजनों का आरोप है कि रूचि के जीजा ने ही दोनों की हत्या कर शवों का फंदे से लटका दिया, ताकि इसे

आत्महत्या का रूप देकर पुलिस को गुमराह किया जा सके। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी दक्षिण प्रवीण रंजन सिंह और महामुदाबाद सीओ सतीश चंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की जांच पड़ताल कर बुलाया गया। एसपी दक्षिण ने कहा- प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। अब तक परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई होगी।

संक्षिप्त डायरी

गैंगस्टर एक्ट के तीन गुनाहगारों को चार-चार साल की सख्त सजा के साथ ही पन्द्रह हजार रुपये का हुआ जुमाना

संवाददाता

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2008 में दर्ज हुये गैंगस्टर एक्ट के मामले में जरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पथखुरी निवासी अभियुक्त देवेन्द्र, हरसहाय सहित प्रमोद को हमीरपुर के एफटीसी फस्ट गैंगस्टर अदालत के स्कालर जज मनोज कुमार शासन ने चार-चार साल की सख्त सजा के साथ ही पन्द्रह हजार रुपये का किया जुमाना, जबकि इस मामले की जांच फतेहपुर डीसीआरवी के तत्कालीन एस आई रमेश चन्द्र ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। गौरतलब है कि जरिया थाना क्षेत्र

एडीजीसी- सुशील कुमार त्रिपाठी

ग्राम पथखुरी निवासी अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र बाबूराम, हरसहाय पुत्र रामकुमार दर्जा सहित प्रमोद पुत्र जगन्नाथ अहिरवार के खिलाफ गिराह बनाकर अपने साथियों के भौतिक और आर्थिक फायदे के लिये आम लोगों में डर और खौफ पैदा करने के मामले में जरिया थाने में अं.सं-0-1475/2008 धारा22/3 गैंगस्टर के तहत 23 अक्टूबर 2008 को मामला दर्ज किया गया था, जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत 20 नवंबर 2024 को हमीरपुर की एफटीसी फस्ट गैंगस्टर कोर्ट के स्कालर जज मनोज कुमार शासन ने तीनों अभियुक्तों को गुनाहगार मानते हुये चार-चार साल की सख्त सजा के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का किया जुमाना। जबकि गैंगस्टर एक्ट के इस संगीन मामले में अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुये एडीजीसी सुशील कुमार त्रिपाठी ने अदालत से तीनों अभियुक्तों को सख्त सजा देने की मांग की थी।

चार साल की सख्त सजा के साथ ही ग्यारह हजार का हुआ जुमाना



संवाददाता

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की सदर कोतवाली में अं.सं-0-290/2022 धारा376,450,323,506 आईपीसी सहित 3(2)5,3(1)द एएसोएस्टी एक्ट में रमेडो डार्डा निवासी अभियुक्त किशन यादव पुत्र गनेश यादव के खिलाफ 20 सितंबर 2022 में पीड़ित के घर में घुसकर जातिभूचक लाफ़ों के इस्तेमाल के साथ ही जान से मारने की धमकी देने के मामले में दर्ज किया गया था, जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत 20 नवंबर 2024 को हमीरपुर की एफटीसी एस्टी एक्ट अदालत के स्कालर जज सुशील कुमार खरवार ने अभियुक्त किशन यादव को धारा-452,323,506 आईपीसी सहित 3(2)5, एससी/एसटी एक्ट के तहत गुनाहगार मानते हुये चार साल की सख्त सजा के साथ ही ग्यारह हजार रुपये का किया जुमाना। हालांकि इस मामले की जांच पूरी करते हुये तत्कालीन सीओ सदर रवि प्रकाश ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, वहीं अभियोजन की तरफ से इस मामले की जबरदस्त पैरवी करते हुये विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने अदालत से अभियुक्त को सख्त सजा देने की मांग की थी।

हमीरपुर की जरिया पुलिस ने अवैध असलहे के साथ दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार



संवाददाता

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की जरिया पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्र के ग्राम कछवाकला निवासी 24 वर्षीय अभियुक्त हिमांशु पुत्र कैलाश राजपूत, जबकि 27 वर्षीय अभियुक्त रामनेश पुत्र चन्द्रशेखर राजपूत को एक अवैध देशी तमंचा, जबकि 3 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जरिया थानाध्यक्ष भरत कुमार ने बताया कि पकड़े गये दोनों अभियुक्तों के खिलाफ जरिया थाने में मु.अं.सं-0-298/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया, जबकि अदालत ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। जबकि दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खासतौर से दिलीप श्रीवास्तव, एस आई रोहित यादव सहित हैड कांस्टेबल शिवेन्द्र सिंह मौजूद रहे।

मदद कर 5 साल की बच्ची की बचाप जान: पिता ने लोगों से की अपील



बस्ती। बनकटी स्थित देउमी गांव के पंकज कुमार अपनी पांच साल की बेटी की जान बचाने के लिए भटक रहे हैं। बिटिया गंभीर किडनी की बीमारी से जूझ रही है। अब तक के इलाज में पंकज की सारी जमा-पूजी खत्म हो चुकी है। आर्थिक तंगी से बेहाल पिता ने अब लोगों और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिटिया की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इलाज के लिए मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा। मुख्यमंत्री और सभी लोगों से विनती करता हूँ कि मेरी बच्ची को बचाने में मदद करें, रं पंकज ने रुंधे गले से कहा। पंकज की बेटी पिछले तीन साल से किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि छह महीने तक दिल्ली में अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस दौरान बच्ची का डायलिसिस भी हुआ। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, एम्स, और लखनऊ जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज करने के बाद भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। अब डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया है। पंकज बताते हैं कि सबसे पहले बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में शुरू हुआ था। यहाँ हालत बिगड़ने पर उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और फिर एम्स भेजा गया।

लखनऊ में गर्लफ्रेंड के सामने लगाई फांसी, मौत



लखनऊ। प्रेमिका के सामने प्रेमी ने फांसी लगा ली। इसके बाद प्रेमिका ने भी नौद की गोलियों का ओवरडोज लेकर जान देने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। वहीं लड़की युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला पारा इलाके में स्थित एक होटल का है। परिजन और दोस्त तलाशते हुए एक होटल के पास पहुंचे तो युवक की बाइक मिली। होटल में पुछताछ करने पर पता चला कि युवक एक लड़की के साथ कमरे में रुका है। दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो मारुटर की से लॉक खोला गया। कमरे में युवक पंखे के सहारे प्रेमिका के दुपट्टे से फांसी पर लटका

था, जबकि युवती बेड पर बेसुध पड़ी थी। पारा के डॉक्टर खेड़ा का रहने वाला अभिषेक वर्मा (25) और उसकी गर्लफ्रेंड पुरानी डीजल टंकी के सामने होटल क्राउन इन में बुधवार दोपहर पहुंचे थे। देर रात घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद परिजन और दोस्तों ने इलाके में खोजबीन शुरू की। होटल क्राउन इन के सामने दोस्तों को युवक की बाइक मिली थी। परिजनों का कहना है कि अभिषेक की शादी तय हो चुकी थी। दिसंबर में शादी होनी थी। इसकी जानकारी पर उसकी प्रेमिका ब्लैकमेल करने लगी थी। वह इस सबसे परेशान हो गया था। लड़की ने ही बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है।

उद्योगों को खड़ा करने के लिये बैंक लोन देने में टालमटोल न करें: जिलाधिकारी



संवाददाता
हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में व्यापार और उद्योग बन्धुओं के साथ जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मीटिंग हॉल में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने व्यापारी बंधुओं की परेशानियों को सुनकर उनके नियमानुसार निस्तारण के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर क्षेत्र, बाजार में अन्ना पशुओं के घूमने से दुर्घटनाओं की आशंका रहती है इसलिए अभियान चलाकर नगर क्षेत्र में घूमने वाले अन्ना पशुओं को गोशालाओं में संरक्षित

किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर, बाजार में अन्ना पशु बंधुओं की बैठक में जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल के प्रकरणों एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पीएम रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले आवेदनों को किसी भी दशा में पेंडिंग न रखा जाए, उनको नियमानुसार स्वीकृत कर समय से डिस्बर्स किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं तथा निवेश व निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं। बैंकों द्वारा

विभाग संयुक्त तौर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाये। उद्योग बंधुओं की बैठक में जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल के प्रकरणों एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पीएम रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले आवेदनों को किसी भी दशा में पेंडिंग न रखा जाए, उनको नियमानुसार स्वीकृत कर समय से डिस्बर्स किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं तथा निवेश व निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं। बैंकों द्वारा

उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण देने में टालमटोल न किया जाए, न ही अनावश्यक रूप से ऋण आवेदन निरस्त किए जाएं। जनपद में अधिकधिक निवेश आकर्षित करने हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएं, इससे जनपद में रोजगार तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कहा कि उद्योगियों की हर संभव मदद की जाए। बैठक में एडीएम न्यायिक डॉ नागेंद्र नाथ यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सदर पवन प्रकाश पाठक, एसडीएम राठ अभिमन्यु कुमार, एसडीएम मौदहा राजकुमार गुप्ता, जौएमडीआईसी रवि वर्मा सहित अधिकारी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।

गोरखपुर में बनेगा हाई-टेक डोमेस्टिक हेजार्डस प्लांट

7 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा हाईटेक प्लांट, खतरनाक कचरे का होगा निस्तारण

गोरखपुर। सहजनवा क्षेत्र के सुथनी ग्रामसभा में 40 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड गारबेज सिटी परियोजना के तहत एक अत्याधुनिक डोमेस्टिक हेजार्डस प्लांट की स्थापना की जा रही है। इस प्लांट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य घरेलू खतरनाक कचरे का सुरक्षित निपटान और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परियोजना के तहत भूमि पूजन संपन्न हुआ। प्लाजा तकनीक पर आधारित इस प्लांट का निर्माण, संचालन और रखरखाव रूड्ड फैसेलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म को सौंपा गया है। भूमि पूजन के दौरान फर्म की डिप्टी उएड नीतिका पाण्डेय ने बताया कि एक साल के भीतर प्लांट का संचालन शुरू हो जाएगा। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला यह प्लांट प्रतिदिन 5 टन घरेलू खतरनाक कचरे का निपटान



करेगा। नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने बताया कि यह परियोजना गोरखपुर को हगारबेज फ्री सिटीह्क का दर्जा दिलाने के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। इसके अलावा, प्लांट कचरे के सुरक्षित निपटान, रिसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। घरेलू खतरनाक कचरा उन उत्पादों से बनता है, जो

विषैले, ज्वलनशील या विस्फोटक होते हैं। इनमें पेंट, पेट थिंर, कीटनाशक, उर्वरक, गैसोलिन, बैटरी, फर्नीचर पॉलिश, ड्रेन ओपनर और ओवन क्लीनर जैसे पदार्थ शामिल हैं। इनका अनजान तरीके से उपयोग न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इन उत्पादों के सुरक्षित निपटान का पूरा तह वैज्ञानिक और प्रभावी बनाया जा सके।

डिप्टी उएड नीतिका पाण्डेय ने कहा कि प्लांट का निर्माण एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण के बाद अगले दो वर्षों तक फर्म को इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्लांट गोरखपुर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की दिशा में एक नई क्रांति लेकर आएगा। मुख्य अभियंता संजय चौहान के मुताबिक, यह प्लांट पर्यावरण संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। घरेलू खतरनाक कचरे का सुरक्षित निपटान न केवल प्रदूषण कम करेगा, बल्कि रिसाइक्लिंग और कचरे से संसाधन पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देगा। परियोजना के तहत सटीक निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे कचरा प्रबंधन को पूरी तरह वैज्ञानिक और प्रभावी बनाया जा सके।

लखनऊ में कार ने स्कूटी को आधा किमी घसीटा



लखनऊ। एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। घटना के बाद स्कूटी कार के बोनट में फंस गई, जिसे कार सवार आधा किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। घटना एफआईआर इलाके में आउटर रिंग रोड किसान पथ पर हुई। बाइक सवार अन्य युवकों ने कार का पीछ कर वीडियो बना ली और पुलिस को सूचना दी। मौके पर कल्ली पश्चिम पुलिस



चौकी प्रभारी प्रभात बलियान, रजित मिश्रा और कॉन्स्टेबल शिवम चौधरी टीम के साथ पहुंचे। कार सवार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं।

छह साप्ताहिकी उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम शुभारंभ

संवाददाता
कुशीनगर। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार एवं भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, ईडीआईआई, अहमदाबाद के शाखा कार्यालय द्वारा कुशीनगर स्थित वत्स कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में छः साप्ताहिकी उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिनको उद्यमिता के मुख्य विषयों जैसे- उद्यमिता के गुण, उद्यमिता बनने के लाभ, उद्यम अवसरों की पहचान एवं उनका चयन, उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया, समस्या समाधान, विपणन, किस कार्य के लिए किससे मिले,



के.वी.आई.बी के.वी.आई.सी एवं जिला उद्योग केन्द्र बैंक आदि के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, ऋण प्रक्रिया, उपलब्धि प्रेरणा, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, लेखा एवं आव प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपस्थित खादी

ग्रामोद्योग बोर्ड, कुशीनगर के सहायक प्रबंधक श्री के एम पांडेय ने अपने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा प्रतिभागियों को अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित वत्स इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग

एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निदेशक मनोज कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण चला रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ई.डी.आई.आई. द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का पूरा

लाभ उठा सकेंगे और अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने पूर्व में अपने यहां आयोजित इसी प्रकार के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि ईडीआईआई बार अकाउंटेंसी पर आधारित कार्यक्रम चलाया गया था। उक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई प्रतिभागियों ने अपना स्वयं का कार्य शुरू कर दिया है, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इसी प्रकार आप भी सफल हों। यही मेरी कामना है। ई.डी.आई.आई. के परियोजना अधिकारी विजय कुमार पांडेय ने कहा कि परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे युवक-युवतियों को नौकरी मिलना काफी कठिन होता है। ऐसे में स्वरोजगार करके

हम न केवल अपने लिए रोजगार सृजित करेंगे बल्कि दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। वहीं इस कार्य में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ईडीआईआई के महानिदेशक प्रोफेसर सुनील शुक्ला जी का पैतृक निवास भी कुशीनगर जिले में है और उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारे देश और प्रदेश के साथ-साथ कुशीनगर के लोग भी अधिक से अधिक उद्यमिता को अपनाएं और स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों के माध्यम से स्वरोजगार विकसित करें। इससे युवाओं का पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।

संक्षिप्त समाचार

हमारे नेता कतर छोड़ नहीं गए तुर्की, इजरायल के दावे पूरी तरह से अफवाह-हमास



गाजा, एजेंसी। हमस ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि उसके कुछ नेता कतर से तुर्की चले गए हैं। एक आधिकारिक बयान में, हमस के सूत्रों ने सोमवार को कहा कि इजरायली मीडिया द्वारा फैलाए गए दावे पूरी तरह से अफवाह हैं जिन्हें इजरायल समर्थ-समय पर बढ़ावा देने का प्रयास करता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, रिवार को इजरायली मीडिया ने खबर दी कि विदेश में स्थित हमस के कई नेता हाल ही में कतर से तुर्की चले गए हैं। इससे पहले सोमवार को तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजरायली मीडिया की रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा कि हमस के राजनीतिक व्यूरो के तुर्की में स्थानांतरित होने के दावे सच्चाई को नहीं दर्शाते हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तत्काल युद्धविराम लागू करने और मध्य पूर्व में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने की अपील की। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, यूएन चीफ ने यह बात परमाणु हथियारों और अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थापना- विषय पर सम्मेलन के पांचवें सत्र में एक वीडियो संदेश में कहा। गुटेरेस ने कहा कि इस तरह के क्षेत्र का विचार दशकों पुराना है, लेकिन क्षेत्रीय संघर्षों और तनावों के चरम पर पहुंचने के साथ, यह लक्ष्य दिन-प्रतिदिन और अधिक जरूरी होता जा रहा है। यूएन महासचिव ने कहा कि एक साल से अधिक समय से गाजा एक विनाशकारी दौर से गुजर रहा है। यह संकट पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की चेतावनी दे रहा है। इस बीच हम सभी लेबनान में बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। 17 अक्टूबर इजरायल ने हमस के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी गुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमस के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनीयों की मौत हुई है। इसके साथ ही इजरायली सेना 23 सितंबर से लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रही है। उसने सीमा पार एक सीमित जमीनी अभियान भी चलाया है, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह को कमजोर करना है।

डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूर्व सीईओ बनने की अमेरिकी की शिक्षा मंत्री, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान
वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार विभागों का बंटवारा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शिक्षा विभाग का निम्ना लोकप्रिय डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की सीईओ और पेशेवर कुश्ती खिलाड़ी लिंडा मेकमोहन को सौंपा है। इससे पहले वह अरबपति एलन मस्क समेत कई बड़े नामों को सरकार का काम सौंप चुके हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने मेकमोहन को शिक्षा विभाग का मंत्री नामित किया है। हालांकि, इससे पहले ही वह ट्रंप सरकार का हिस्सा रह चुकी हैं। मेकमोहन ने 2017 से 2019 तक ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लघु व्यवसाय प्रशासन का नेतृत्व किया था। वह कनेक्टिकट में अमेरिकी सीनेट के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दो बार चुनाव लड़ीं लेकिन असफल रहीं। मेकमोहन ने 2009 से एक साल तक 'कनेक्टिकट बोर्ड ऑफ एजुकेशन' में काम किया और कनेक्टिकट में 'सेकेंड हाट यूनिवर्सिटी' के 'बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' में कई साल बिताए। शिक्षा जगत में उन्हें अपेक्षाकृत अज्ञात माना जाता है, हालांकि उन्होंने 'चार्टर स्कूलों' और 'स्कूल चॉइस' के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका में 'चार्टर स्कूल' सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्कूल होते हैं जो अपने स्थानीय जिले से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। 'स्कूल चॉइस' शिक्षा के विकल्पों को दर्शाता है जिसके तहत छात्रों और परिवारों को सार्वजनिक स्कूलों के विकल्प चुनने की अनुमति मिलती है। मेकमोहन ने अमेरिकी सीनेट के चुनाव के लिए 2009 में डब्ल्यूडब्ल्यूई को आविर्भाव दे दिया था। उन्हें ट्रंप के लिए बड़ा डोनेशन देने वालों में गिना जाता है।

तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराया, यूरोपीय देशों ने भोजन, पानी जमा करने को कहा

ओस्लो, एजेंसी। नॉर्वे ने आपातकालीन पुस्तिकाएं भी जारी कीं जिसमें लोगों को संपूर्ण युद्ध सहित किसी आपातकालीन स्थिति में एक सप्ताह तक प्रबंधन करने की सलाह दी गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन-रूस युद्ध को खतरनाक रूप से बढ़ाते हुए, यूक्रेनी बलों ने मंगलवार देर रात रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में छह अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें दागीं। इसी मौकों द्वारा एक बड़े उकसावे के रूप में देखा जाएगा और एक जोरदार जवाबी कार्रवाई की संभावना है। कई नाटो देश अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। परमाणु युद्ध का खोपनाक खतरा पहले से कहीं ज्यादा नजदीक खतरा आ रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस सीमा को कम कर दिया जब रूस परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता था। यह तब हुआ जब यूक्रेन ने रूस के अंदर लक्ष्यों पर लंबी दूरी की छह अमेरिकी मिसाइलें दागीं। नाटो देशों ने युद्ध की आशंका गहराने की आशंका को भांपते हुए अपने नागरिकों को पर्व जारी किए, जिसमें उन्हें युद्ध की तैयारी करने की सलाह दी गई।

ब्रिटेन में हजारों किसानों ने ट्रैक्टरों सहित संसद के बाहर किया प्रदर्शन

लंदन, एजेंसी। हजारों ब्रिटिश किसानों ने मंगलवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने एक नए कर नियम के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है कि यह नियम पारिवारिक खेती को बर्बाद कर देगा। किसान बेनर, टॉय ट्रैक्टर और नारों के साथ सड़कों पर उतरे। सरकार के फैसले से गुस्सा किसानों का कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सरकार ने हाल ही में बजट में एक पुराने कर छूट नियम को समाप्त करने का फैसला किया है। यह नियम कृषि भूमि को इन्हेरिटेन्स टैक्स से छूट देता था। अप्रैल 2026 से, 10 लाख पाउंड (लगभग 13 करोड़ रूपए) से अधिक मूल्य वाली कृषि भूमि पर मालिक की मृत्यु के बाद इसे अगली पीढ़ी को देने पर 20 प्रतिशत टैक्स लागेगा। किसानों का कहना है कि यह नियम उनके लिए अंतिम झटका साबित होगा। प्रदर्शन के सह-आयोजक ओल्लि हैरिसन ने कहा, हर कोई नाराज है। हम सड़कों को जाम करने और फ्रांस के किसानों जैसे विरोध की तैयारी में हैं। किसानों ने ड्युर्जिंग स्ट्रीट के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ ट्रैक्टरों पर फाइनेल स्ट्रैंड और नो फार्मर्स, नो फूड जैसे नारों के पोस्टर लगे हुए थे। बच्चों ने छोटे ट्रैक्टरों के साथ संसद स्क्वायर के आसपास मार्च निकाला। मशहूर



टीवी होस्ट और किसान जेरेमी क्लार्कसन भी इस रैली में शामिल हुए। 1,800 किसानों को नेशनल फार्मर्स यूनियन (एनएफयू) ने संसद के अंदर जाकर सांसदों से बात करने का मौका दिया। एनएफयू के अध्यक्ष टॉम ब्रैडशॉ ने कहा, यह नीति ब्रिटेन की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। किसानों का कहना है कि ब्रेक्सिट, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अस्थिरता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति

पहले से ही खराब है। अब यह नया कर नियम उनके लिए असहनीय है। किसानों की औसत आय पहले से ही कम हो गई है। उदाहरण के लिए, मवेशी पालने वाले किसानों की औसत आय केवल 17,000 पाउंड (21 लाख रूपए) है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार का कहना है कि 75 प्रतिशत किसानों पर यह कर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, कई छूट के कारण किसान दंपति अपनी संपत्ति का 30 लाख

पाउंड (39 करोड़ रूपए) तक टैक्स-मुक्त हस्तांतरण कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्री की औसत आय पहले से ही कम हो गई है। उदाहरण के लिए, मवेशी पालने वाले किसानों की औसत आय केवल 17,000 पाउंड (21 लाख रूपए) है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार का कहना है कि 75 प्रतिशत किसानों पर यह कर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, कई छूट के कारण किसान दंपति अपनी संपत्ति का 30 लाख

रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल के विरोध में स्लोवाकिया, पीएम फिको ने की अमेरिकी फैसले की आलोचना

वाटिस्लावा, एजेंसी। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने सोमवार को यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल करने का विरोध किया है। यह जानकारी स्लोवाकिया गणराज्य की समाचार एजेंसी (टोएएसआर) ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से बताया कि यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो

बाइडेन ने अपनी प्रशासनिक नीति में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत बाइडेन ने कीव को रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। एसोसिएटेड प्रेस, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट सहित अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने दो अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस हरी झंडी से यूक्रेनी सेना को अमेरिका निर्मित एटीएसएमएस मिसाइलों को पहली बार उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। टोएएसआर की रिपोर्ट के अनुसार, फिको ने देश के विदेश मंत्री जुराज ब्लानर और रक्षा मंत्री रॉबर्ट कालिनाक को इस कदम का समर्थन करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कार्यालय ने फिको के हवाले से कहा, यह तनाव में अभूतपूर्व वृद्धि है। बता दें कि सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया की ओर से युद्ध में मास्को की मदद के लिए हजारों सैनिकों की कथित तैनाती के जवाब में यूएस प्रेसिडेंट ने यह फैसला लिया है। सोल और वाशिंगटन दोनों ने इस बात का दावा कर रहे हैं कि रूस के पश्चिमी सीमावर्ती कर्सक क्षेत्र में तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की लंबे समय से यह मांग करते आए हैं कि रूस के अंदर लक्ष्यों को धरने के लिए कीव को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (एटीएसएमएस) का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। एटीएसएमएस 300 किमी (186 मील) तक जा सकती है।

रूस ने भारत-चीन संबंधों के लिए समर्थन दोहराया, कहा- हर संभव तरीके से योगदान करने के लिए तैयार

मास्को, एजेंसी। पेसकोव ने पुष्टि की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की योजना बनाई जा रही है, फिलहाल तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पेसकोव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम उनकी यात्रा की सटीक तारीखों पर काम करेंगे। बेशक, प्रधान मंत्री मोदी की दो रूस यात्राओं के बाद, अब हमारे पास राष्ट्रपति की भारत यात्रा है, इसलिए हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह यात्रा 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए मास्को की प्रतिबद्धता दोहराई। पेसकोव ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने के लिए तैयार हैं। एएनआई से बात करते हुए, पेसकोव ने रूस के तटस्थ रुख पर जोर दिया और रूस के कजान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिन्पिंग के बीच हालिया द्विपक्षीय बैठक के दौरान एक मेजबान के रूप में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला। हमें खुशी है कि दोनों नेताओं को कजान में अपनी द्विपक्षीय बैठक करने का अवसर मिला। यह दुनिया में हर किसी के लिए वास्तव में अच्छी खबर थी। लेकिन फिर, यह भारत और चीन की एक द्विपक्षीय पहल थी।

पूर्व कनाडाई पीएम हार्पर ने टूटो सरकार को फटकारा, कहा- खालिस्तानियों और जिहादियों को बढ़ावा देना बंद करो

टोरंटो, एजेंसी। पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कनाडा की टूटो सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह खालिस्तानियों और जिहादियों जैसे विभाजनकारी समूहों को बढ़ावा देना बंद करे। हार्पर, जो 2006 से 2015 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे, ने कनाडा की आब्रजन और विदेशी नीतियों की तीखी आलोचना की। हार्पर ने यह टिप्पणी अब्राहम स्लॉबल पीएस इनिशिएटिव (एजीपीआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस दौरान उन्होंने एजीपीआई के संस्थापक और सीईओ एवी बेनलन के साथ चर्चा की। बेनलन ने नेशनल पोस्ट में प्रकाशित अपने लेख में हार्पर के बयान को उद्धृत करते हुए लिखा कि हार्पर ने कहा, हमें जिहादियों, यहूदी विरोधियों,

खालिस्तानियों, तमिल टाइगर्स और अन्य विभाजनकारी समूहों को बढ़ावा देना बंद करना होगा। हमें अपनी आब्रजन प्रणाली पर सख्त सवाल उठाने की जरूरत है कि हम लोगों को कैसे चुनते हैं। हार्पर का यह बयान ऐसे समय आया है जब कनाडा और भारत के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत थे, लेकिन वर्तमान में दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। तनाव तब बढ़ा जब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाए। भारत ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज कर दिया और ट्रूडो से सबूत मांगे, जो उन्होंने अभी तक पेश नहीं किए



हैं। हार्पर ने खालिस्तानी मुद्दे को कनाडा की नीतियों का हिस्सा बनाने पर सवाल उठाया और कहा कि आब्रजन नीति में सुधार की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थकों के बारे में कहा कि वे पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत समर्थक हिंदू भी पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हालांकि, ट्रूडो को खालिस्तानी समूहों के प्रति नरम रखने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। हार्पर ने कनाडा की आब्रजन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह नीति उन लोगों को शामिल कर रही है जो विभाजनकारी और हिंसक विचारधारा रखते हैं। उन्होंने एजीपीआई कार्यक्रम में यह भी कहा कि कनाडा को अपनी नीतियों को संतुलित करना होगा ताकि बहुसंस्कृतिवाद के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा, भारत के जी-20 अनुभव से बहुत कुछ सीखा

रियो डी जेनेरियो, एजेंसी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इंसियो लूला दा सिल्वा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि ब्राजील ने दो दिवसीय जी-20 रियो शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी की दूसरे और अंतिम दिन की बैठक के शुरुआत में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में द्विपक्षीय बैठक में उनका स्वागत किया।



बैठक के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भूख और गरीबी को खिलाना वैश्विक गठबंधन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और पिछले वर्ष जी-20 के आयोजन के लिए उन्हें बधाई दी। लूला ने कहा कि ब्राजील ने रियो शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारतीय अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। बैठक के दौरान, राष्ट्रपति लूला ने 2025 में सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा

करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अगले साल राष्ट्रपति लूला और प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने में खुशी होगी और वह 2025 लूला के आयोजन के लिए उन्हें बधाई दी। लूला ने कहा कि ब्राजील ने रियो शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारतीय अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। बैठक के दौरान, राष्ट्रपति लूला ने 2025 में सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा

द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। हमने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मूल्यांकन किया और ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। पीएम मोदी ने जी-20 के कार्य को जारी रखने और समूह के एजेंडे के मुद्दों पर प्रगति के लिए ब्राजील की अध्यक्षता की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने जैव ईंधन, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की। रियो शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष के जी-20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाता है, जहां विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बैठक में ब्राजील के मंत्री माउरो विष्टा (विदेश मामलों), फर्नांडो हेराद (वित्त), एलेक्जेंडर सिल्वेरा (खान और ऊर्जा), लुसियाना स्टोस (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), साथ ही विकास, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के कार्यकारी सचिव मार्सिओ एलियास रोजा ने भी भाग लिया।

पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान की लंबी लड़ाई का अंत नहीं, सक्रिय मामले 50 तक पहुंचे

इस्लामाबाद, एजेंसी। पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए पाकिस्तान का संघर्ष जारी है। खैबर पख्तूनख्वा (केपी) और बलूचिस्तान प्रांतों से नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को देश में सक्रिय पोलियो मामलों की कुल संख्या 50 तक पहुंच गई। अब तक बलूचिस्तान से कम से कम 24 मामले, सिंध से 13, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) से 11, पंजाब और इस्लामाबाद से एक-एक मामले सामने आए हैं। मंगलवार को एक बच्ची में बलूचिस्तान पोलियोवायरस (डब्ल्यूपीवी1) पाया गया, जो केपी के टैंक जिले से पोलियो वायरस का दूसरा मामला है।

पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पोलियो टीकाकरण अभियान का विरोध भी हो रहा है और यहां तक ??कि स्वास्थ्य कर्मियों पर भी हमला हुआ है जिसमें लोगों की जान भी गई। टारगेटेड अटैक के खतम होने का कोई संकेत नहीं दिखने के कारण, पोलियो टीकाकरण अभियान को सूचारू रूप से चलाना लगभग असंभव हो गया है, जिससे बच्चों के संक्रमित होने की संभावना बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विभिन्न भागों में पोलियो के मामलों में उत्साहजनक गिरावट देखी गई है। हालांकि उसने चेतावनी दी है कि नवीनतम मामलों का पता चलना एक खतरनाक और चिंताजनक संकेत है। यह दर्शाता है कि कई जिलों में बच्चे अभी भी जोखिम में हैं। पाकिस्तान और पड़ोसी अफगानिस्तान, दुनिया के दो ऐसे देश हैं जहां पोलियो अभी भी स्थानिक है। अतीत में, पाकिस्तान ने सालाना 300 मिलियन से अधिक औसत वैक्सीन लगाए हैं। लेकिन यह बीमारी देश में अभी भी व्याप्त है।

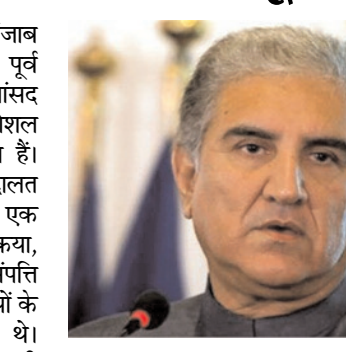
कई विश्लेषकों ने पोलियो वायरस के प्रसार को संभालने में पाकिस्तान सरकार की निरंतर नाकामी पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान के प्रति विरोध तब बढ़ा जब अमेरिकी जासूसी एजेंसी सीआईए ने देश में अल-कायदा नेता ओसाમા बिन लादेन का पता लगाने के लिए एक फर्जी हेपेटाइटिस टीकाकरण अभियान चलाया।

दुनिया के सबसे वॉन्टेड आतंकवादियों में से एक, बिन लादेन को 2011 में केपी के एबटाबाद में घुसने वाली सील के ऑपरेशन में मार दिया गया। कई धार्मिक नेताओं का यह भी मानना ??है कि पोलियो टीकाकरण की बूढ़ों में सुअर का मांस और शराब के अंश होते हैं, जो इस्लाम में निषिद्ध है।

पाकिस्तान की अदालत ने दंगों को लेकर पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी पर तय किए आरोप

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और 20 अन्य लोगों के खिलाफ नौ मई 2023 के दंगों के संबंध में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उपाध्यक्ष कुरैशी ने सोमवार को कोर्ट लखत जेल में सुनवाई के दौरान तय किए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ये मामले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेतृत्व को दबाने के लिए गढ़े गए हैं।

जिन वरिष्ठ नेताओं पर आरोप तय किए गए हैं उनमें पीटीआई की पंजाब इकाई के अध्यक्ष यास्मीन रशीद, सीनेटर एजाज चौधरी, पंजाब के पूर्व राज्यपाल उमर सरफराज चौमा, पूर्व प्रांतीय मंत्री मियां महमूदुर राशिद, पूर्व सांसद आलिया हमजा, रूबीना जमील तथा सोशल मीडिया कार्यकर्ता सनम जावेद शामिल हैं। सुनवाई की अध्यक्षता आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश मंडर अली खान ने की। एक विशेष अभियोजक ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें थाने पर हमला करने, सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाने और कानून प्रवर्तन कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे आरोप शामिल थे। अदालत के अधिकारी के मुताबिक, सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के पास अपने दावों को पुष्ट करने के लिए सबूतों का अभाव है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 25



नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अपने गवाह पेश करने का निर्देश दिया। नौ मई 2023 को खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस), मियांवाली एयरबेस और

फैसलाबाद में आईएसआई भवन समेत एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर भी पहली बार भीड़ ने हमला किया। पत्रकारों से बात करते हुए कुरैशी ने खान के प्रति अपनी निष्ठा जतायी। खान अगस्त 2023 से 200 से अधिक मामलों को लेकर जेल में बंद हैं। कुरैशी ने इन मामलों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि इन्हें पीटीआई नेतृत्व को दबाने और उन्हें अवैध रूप से जेल में रखने के लिए गढ़े गए हैं। कुरैशी ने पीटीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों से 24 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विरोध मार्च में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह रैली राजनीतिक कैदियों की आजादी, स्वतंत्र न्यायाधिकार की बहाली और इमरान खान की रिहाई के लिए है।

इरान में जेल में बंद नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ीं: तेहरान, एजेंसी। इरान में जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी एक जटिल सर्जरी से गुजरतीं, जिसके तहत उनके दाएं पैर की एक हड्डी का कुछ हिस्सा कैप्सर की आशंका के चलते हटा दिया गया। हालांकि, अधिकार समूहों के मुताबिक, नरगिस को सर्जरी के महज दो दिन बाद वापस जेल भेजा दिया गया, जिससे उनकी सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) को भेजे गए 40 से अधिक अधिकार समूहों के हस्ताक्षर वाले एक पत्र में नरगिस को उन आरोपों में सुनाई गई जेल की सजा से तत्काल निकालकर फलों पर रिहा करने का आग्रह किया गया है।

सिरसा के रानियां में स्कूल वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, नाबालिग सहित 4 लोग घायल



सिरसा । सिरसा के रानियां में स्कूल वैन पर सरेआम गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। पुरानी रजिस्ट्रार और साइड नहीं देने पर पिता और पुत्र ने स्कूल वैन पर फायरिंग की। आरोपी पिता पुत्र घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों की तलाश में जुट गई। जानकारी के मुताबिक घटना घटाना सिरसा के नराना थंड गांव के पास की है। यह विवाद गाड़ी और ट्रैक्टर के करीब 50 मीटर की दूरी पर हुआ। विवाद बढ़ने पर आरोपी पिता पुत्र ने गोलियां आरोपी पिता पुत्र घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हैं। स्कूल वैन में दर्जनो बच्चे सवार थे। घटना में एक स्कूल की बच्चे सहित 4 लोग बुरी तरह से घायल हैं। सभी को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

पानीपत : 40 लाख रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार, गैंगरेप मामले में समझौते के लिए थे पैसे



पानीपत । जिले में दुष्कर्म मामले में आरोपियों को ब्लैकमेल कर समझौता करवाने के नाम पर 45 लाख रुपये जब्त करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 40 लाख रुपये बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक लोकेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में सीआईए व पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी की पहचान नेमपाल निवासी काबड़ी के रूप में हुई।

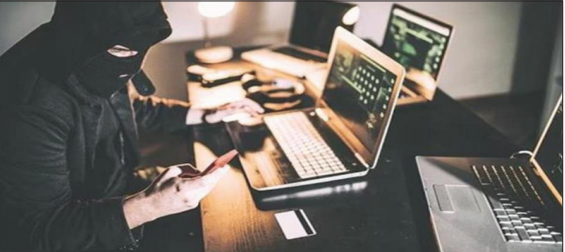
ये है मामला

इस मामले को लेकर एसपी लोकेन्द्र सिंह ने बताया कि गत दिनों एसपी ऑफिस में थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र के व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया था कि उसके भतीजे के खिलाफ 22 अक्टूबर को थाना पुराना औद्योगिक में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप किया और फिर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन केस दर्ज होने के 2 या 3 दिन के बाद काबड़ी निवासी नेमपाल अपनी पत्नी के साथ उससे और उसके भाई से मिलकर कहने लगा वह केस में फैसला करवा देगा, जिसकी एवज में उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। जब पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे लड़कों को जेल से निकलने नहीं देंगे। डर के मारे उन्होंने पैसे देने की हान भर दी। आरोपी नेमपाल 31 अक्टूबर को गांव में एक प्रार्थना डीलर के ऑफिस में आया और समझौते की एवज में 1 करोड़ रुपये की मांग की। लेकिन उन्होंने इतने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद 50 लाख में सौदा तय हुआ। मौके पर उन्होंने उसे 45 लाख रुपये दिए। आरोपी नेमपाल अब फिर उनसे 5 लाख रुपये मांग रहा है। आरोपी धमकी दे रहा है की जब तक 5 लाख रुपये नहीं दोगे तो वह मुकदमा वापस नहीं लेंगे। इससे हमारा पूरा परिवार दशहमें में है।

आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकार्ड : एसपी

इस मामले में एसपी ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को काबड़ी पलाईओवर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के पास 40 लाख रुपये की नकदी बरामद की है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया उसने 5 लाख रुपये कर्ज चुकाने के लिए दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकार्ड होना पता गया है। आरोपी को खिलाफ अनेक शराब तस्करी, मारपीट, धोखाधड़ी, जानलेवा हमला व अपहरण का प्रयास करने मामले के कुल 13 अभियोग दर्ज हैं। इनमें 12 अभियोग पानीपत के थाना माडल टाउन, थाना पुराना औद्योगिक, थाना शहर में व 1 अभियोग यूपी के शामली जिला में दर्ज हैं। इनमें अधिकतर मामले माननीय न्यायालय में विचारधीन हैं।

10 दिन तक महिला रहनी डिजिटल अरेस्ट इसके बाद क्या हुआ यह जान कर उड़ जाएंगे होश



यमुनानगर । देश में आजकल एक ठगी का नया तरीका चल निकला है, जिसके माध्यम से सीबीआई, ई डी के अधिकारी बनकर लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे वसूल जाते हैं। ऐसा ही एक अलग तरह का मामला यमुनानगर में सामने आया है, जिसमें एक महिला को 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। यमुनानगर की महिला ने साइबर थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया कि 9 नवंबर को उनके पास एक कॉल आया कि हम सीबीआई वाले बोल रहे हैं। आपका आधार कार्ड पर एक सिम जारी हुआ है, जिसमें अकाउंट खोलकर 68 करोड़ की हेरा फेरी की गई है। इसलिए आपको इसमें गिरफ्तार किया जाता है। अधिकारी ने कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट होना चाहते हैं या फिजिकल तो, महिला ने डिजिटल अरेस्ट होने की बात कही, जिस पर सीबीआई बने पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वीडियो कॉल ऑन रखने की आदेश दिए और कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी। अगर वह बैंक में गई तो उस दौरान भी वीडियो कॉल ऑन रुकी गई। 9 नवंबर से 19 नवंबर तक लगातार यह सिलसिला जारी रहा और इस दौरान कुल 13 लाख से अधिक की राशि सीबीआई के अधिकारी बने लोगों ने विभिन्न अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी। इसके लिए बाकायदा सीबीआई के लेटर हेड पर उन्हें क्लॉकसुपर पर लेटर भी भेजा गया। साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया। इसके बाद उन्होंने तुरंत उस ट्रांजेक्शन को सीज करने के लिए विभिन्न बैंकों और अन्य सिस्टम से अनुरोध किया। साइबर थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की कि वह डिजिटल अरेस्ट अथवा अन्य ऐसे किसी भी नए तरह के फॉंड को लेकर किसी झंसे में ना आए और इसकी सूचना तुरंत पुलिस अथवा साइबर थाना को दें। उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई नियम नहीं है, अभी सीबीआई ईडी अधिकारी बनकर अपने आप को ऑफिस में दिखाकर वीडियो कॉल के माध्यम से इस तरह के ब्लैकमेल के मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें डॉक्टर रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों को टारगेट किया जाता है, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।

कुमारी शैलजा ने सीएम नायब सैनी को लिखा पत्र, कर दी बड़ी मांग

चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या और इलाज की सीमित सुविधाएं एक गंभीर मुद्दा हैं। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला जैसे जिलों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिससे मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि हरियाणा के सभी जिलों के सुविधाएं अस्पतालों में कैंसर उपचार की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इससे न केवल मरीजों को प्रदेश में ही उचित इलाज मिल सकेगा, बल्कि उनका समय और संसाधन भी बचेगा।

सांसद कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखे पत्र में कहा कि हरियाणा में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। विशेष रूप से घग्गर नदी के किनारे पड़ने वाले जिले जैसे सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला में सिविल अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपलब्धता के साथ-साथ समुचित उपचार के अभाव में रोगी अपनी बहुमूल्य जान गंवा रहे हैं। बताया गया है कि हरियाणा में हर महीने लगभग 1500 कैंसर रोगी कैंसर से मर रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र सिरसा, जिसमें घग्गर नदी के किनारे पड़ने वाले सिरसा, फतेहाबाद जिले शामिल हैं। इन जिलों के कैंसर रोगियों को या तो पीजीआई रोहतक/ चंडीगढ़/राष्ट्रीय कैंसर

संस्थान, झज्जर में इलाज के लिए जाना पड़ता है, जहां रोगियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उन्हें अपनी बारी और भती होने आदि के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। उनके पास हरियाणा और हरियाणा से बाहर के निजी अस्पतालों जैसे बोकानेर, जयपुर, दिल्ली में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, जो आम आदमी के लिए काफी महंगा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार को सभी कैंसर प्रभावित/प्रभावित जिलों के नागरिक अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए, ताकि उन्हें न केवल उचित और समय पर इलाज मिल सके। उनकी जान भी बच सके और उन पर आर्थिक बोझ भी कम हो। उन्होंने आशा व्यक्त



करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस गंभीर चिंता के मामले पर गौर करेंगे और कैंसर रोगियों के व्यापक हित में जल्द से जल्द कैंसर प्रभावित जिलों के सभी नागरिक अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

'हमारी चिंता छोड़ें, पहले अपना नेता चुन लें', कृष्ण लाल पवार का हड़्डा पर तीखा कटाक्ष

रोहतक । मौजूदा सरकार के दौरान हूँ पहली परिवेदना समिति की बैठक में रोहतक परियोजना समिति के अध्यक्ष विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने अधिकारियों को सीधी चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि विभाग अध्यक्ष को परिवेदना समिति की बैठक में मौजूद रहना अनिवार्य है, अन्यथा सस्पेंड कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी सहयोग करें और जो काम करूंगा उसे सम्मान मिलेगा। वहीं मंत्री कृष्ण लाल पवार ने भूपेंद्र सिंह हड़्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना विधानसभा प्रतिपक्ष नेता ही नहीं बन पा रही तो भाजपा पर सवाल उठाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि न केवल विकास एवं



पंचायत मंत्रालय उनके पास है और मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि प्रदेश के 1000 गांव में पहले फेज के दौरान सभी फिर्ना पक्की की जाएगी और स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

उदयभान द्वारा ईवीएम हैक करने के मामले पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने व अपनी हार की कसक को शांत करने के लिए ईवीएम का राग अलाप रही है। उन्हें अब तो सपने में भी ईवीएम दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1000 गांव में ईलाक़े भी बनेगी तब तक युवा उम्र में पढ़ कर बिना खर्चों पर्वी रोजगार ले सकें। अवैध खनन को लेकर भी मंत्री कृष्ण लाल पवार सख्त नजर आए और उन्होंने कहा कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स अवैध खनन को रोकने के लिए काम करेंगे।

अनिल विज का दावा: महाराष्ट्र व झारखंड में बीजेपी बनाएगी सरकार, कांग्रेस के ईवीएम हैक के आरोपों पर भी किया पलटवार

अंबाला । (अमन कपूर) - महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद अब एफिजेंट पोल आ गए हैं और एफिजेंट पोल में महाराष्ट्र में NDA को बढ़त मिलती नजर आ रही है तो वहीं झारखंड में कटे की टक्कर दिखाई जा रही है जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। बता दें कि जब हरियाणा में चुनाव हुए थे और सभी एफिजेंट पोल कांग्रेस की सरकार बनती बता रहे थे, तब भी अनिल विज ने

कांग्रेस ने एक बार फिर से हरियाणा में 14 सीटों पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया है और आज इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट में जा रही है जिसपर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि ईवीएम कांग्रेस का जीने का सहारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ईवीएम का नाम लेके रोते रहेंगे और तो उनके पास कुछ है नहीं और ये तो हर चुनाव में होता है, जब भी कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को लेकर रोती है।

कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी पर बोलते विज बता दें कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है जिस पर



हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता हैं और कोई नाराजगी वाली बात नहीं है।

प्रधानमंत्री के पानीपत कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव विवेक जोशी ने उपायुक्त से की वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक

कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार: उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया

संस्कार उजाला हरियाणा/हिसार (गरिमा) : हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के 9 दिसंबर के पानीपत के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। मुख्य सचिव ने विशेष तौर पर पार्किंग, जनसुविधाओं व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता को लेकर किसी तरह की कोर कसर नहीं बचनी चाहिए। हमारे पास बेहतरीन करने के लिए काफी समय है। हमें इस कार्यक्रम में मेहनत करके इसे सफल बनाना है। उपायुक्त ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि हम कार्यक्रम की सफलता को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उपायुक्त ने बताया कि सैक्टर 13-17 का चयन कार्यक्रम



के लिए किया गया है। स्थल का वे निरीक्षण करके जायजा ले चुके हैं। कार्यक्रम स्थल कार्यक्रम के दृष्टिगत सही है। संभवतय कार्यक्रम के साथ में दो पार्किंग बनाई जाएगी जहां 1 हजार से ज्यादा बसों की व्यवस्था होगी। संभवतय अलग अलग स्थानों पर दो हेली पैड हैं। जिनका वे मुआयना कर चुके हैं। कार्यक्रम के दृष्टिगत दोनों हेली पैड कार्यक्रम के अनुकूल है। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता को लेकर वे पूरी तरह से निश्चित हैं। कार्यक्रम में प्रदेश भर से महिलाएं शिरकत करेंगी। महिलाओं के बैठने के लिए 35 हजार से ज्यादा

कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर शौचालय, पानी की विशेष व्यवस्था की जा रही है। सभा स्थल में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि दूर-दराज से अपने वाहनों को लेकर आने वालों के लिए संभवतया 31 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी जिसमें एक एकड़ में वीआईपी की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम में पहुंचने वालों को रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा इसके लिए फूड पैकेट की व्यवस्था की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि संभवतय कार्यक्रम की गारंटी को देखते हुए 2 या 3 स्ट्रेज बनाये जाएंगे। जिसमें एक स्ट्रेज

सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए होगा। दो ऐंकर कार्यक्रम में ऐंकरिंग करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता को लेकर आस पास के जिलों के एसएसजी की महिलाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम की कवरेज को लेकर मीडिया के आईकार्ड बनाए जाएंगे। मीडिया के अलावा अन्य 8 तरह के परिचय पत्र भी कार्यक्रम की सुविधा को देखते हुए बनाए जाएंगे। उपायुक्त ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि वे पूर्व के कार्यक्रमों से भी बेहतर कार्यक्रम सफलतापूर्वक करावेंगे। इसको लेकर वे गंभीर हैं व उनका पूरा ध्यान कार्यक्रम की सफलता पर केंद्रित है। इस मौके पर पूर्व सांसद संजय भाटिया, एसपी लोकेन्द्र सिंह, एडीसी डॉ. पंकज, जिला परिषद के सीईओ नरेन्द्र पाल मलिक, सीटीएम टी.नू. पोसवाल, पब्लिक हेल्थ के अधीक्षक अभिषेखा कर्ण बहल, डीएफओ विजय लक्ष्मी आदि मौजूद रहे।

सिरसा को सीएम ने दी मेडिकल कॉलेज की नायाब सौगात, 1010 करोड़ की लागत से तैयार होगा कॉलेज

सिरसा । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को सिरसा में बाबा सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री कुमारी शैलजा ने की। इस मौके पर पूर्व डेप्युटी बाबा सरसाईनाथ के महंत सुरेंद्रनाथ, सिरसा के विधाक गोकुल सैतिया, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, हेलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा, उडैसा के पूर्व राज्यपाल प. गणेशी लाल, स्वास्थ्य विभाग की एसोसिएट सुमित्रा मिश्रा, डॉ. सकेत कुमार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी व अन्य गणमान्यों ने मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने पौधरोपण भी किया है। इसके पश्चात अपने संबोधन में मुख्यमंत्री

नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाबा सरसाईनाथ जी एक महान संत थे। जिन्होंने शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को जीवनदान दिया। उनके नाम पर सिरसा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोग होकर जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 21 एकड़ भूमि में 1010 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज तैयार होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सिरसा में साढ़े पांच एकड़ भूमि पर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया है। पहले हरियाणा में काम धोमा था। मेडिकल कॉलेज भिवानी का काम लगभग पूरा

हो चुका है। डबल इंजन की सरकार ने विकास की रफ्तार को बढ़ाया है। फरीदबाद, पंचकूला, रेवाड़ी में नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सेवा मिले। अब हर गरीब परिवार को मेडिकल सेवाएं मिल रही हैं। पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना दी जा रही है। हरियाणा में चिरायु हरियाणा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 आयु को उम्र के बुजुर्गों के लिए इलाज मुफ्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा में भी योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने बच्चों को नरेश से दूर रखें। किसान भाई पेट्रोलियम का उपयोग कम करें, हमें प्राकृतिक खेती का रास्ता अपनाना चाहिए।



रक्त का कोई विकल्प नहीं साधु राम जाखड़ स्वर्गीय दीपक जाखड़ की पुण्यतिथि पर आईटीआई बरवाला में लगाया रक्तदान शिविर



संस्कार उजाला हरियाणा/ हिसार (गरिमा) : स्वर्गीय दीपक जाखड़ की पुण्यतिथि के अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरवाला के प्रांगण में रक्तदान शिविर एचडीएफसी बैंक बरवाला के सहयोग से लगाया गया इस रक्तदान शिविर में अग्रोहा मेडिकल ब्लड बैंक ऑफिसर रिचा मैन के नेतृत्व में ब्लड बैंक महाराजा अग्रसेन अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की टीम द्वारा रक्त एकत्रित करने संबंधी सेवाएं दी गईं। जिसमें आई.टी.आई स्टूडेंट, स्टाफ और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों व शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रक्तदान करते हुए 94 रक्तदाताओं द्वारा अपनी-अपनी स्वेच्छ से रक्तदान किया गया। इस शिविर में राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी वन में कार्यरत तीन अध्यापकों रविंद्र लोहान, ओमपाल व रविंद्र जांगड़ा द्वारा रक्तदान किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य साधु राम जाखड़ ने सभी रक्तदाताओं और आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और रक्तदान के बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि रक्तदान कर हम जहां एक ओर किसी की जान बचाते हैं वहीं दूसरी ओर इससे आत्म संतुष्टि मिलती है हम सभी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता है। आपके द्वारा दिए गए रक्त से तीन व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। इस दौरान रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस मौके पर. प्राचार्य प्रवीण डाबला, सहप्राचार्य नीरज कुमार, जयपाल वर्मा, दीपक कुमार, अशोक जांगरा, महावीर सिंह, एचडीएफसी बैंक प्रबंधक राजेश कुमार, मनोज कुमार, जोगिंदर सिंह, सज्जन कुमार, पवन कुमार, सतीश कुमार, बर्जिंद्र कुमार, राज कुमार, सचिव जिले सिंह, राकेश कुमार, अनु कुमार, नेहा देवी, सुनीता जाखड़, जिले सिंह शेखावत, उर्मिला बूरा, नीलम सूडा व ऑपरेशन मैनेजर राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।

हरियाणा में नए जिले बनने पर ब्रेक, सरकार ने लगाई रोक...

चंडीगढ़ । हरियाणा में नए जिले, उपमंडल और तहसील बनने को लेकर उठ रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। अब जनगणना के बाद ही इस संबंध में आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में जनगणना शुरू होगी, तब तक सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। वित्तियुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जनगणना का कार्य पूरा होने तक जिला, तहसील और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। बता दें कि गोहाना, हांसी, असंध, मानेसर और डबवाली को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है, जबकि कलानौर और बवानी खेड़ा उपमंडल बनने की दौड़ में शामिल हैं। प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन से पहले जून में तत्कालीन कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर की अध्यक्षता में गठित कमेटी का भी नए विरे से गठन किया जाएगा। इस कमेटी में तत्कालीन वित्त मंत्री जेपी दत्ताल, पंचायत मंत्री महिपाल दांडा और शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा शामिल थे, लेकिन इनमें से महिपाल दांडा को छोड़कर सभी मंत्री चुनाव हार चुके हैं। इसके चलते प्रदेश सरकार को कमेटी का पुनर्गठन करना होगा।

जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में 'निपुण कार्यशाला' की बैठक आयोजित

किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य के प्रति उत्साह और रूचि आवश्यक: जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह विभिन्न तरीकों से कार्य को सकुशल सम्पन्न कराना, आपकी कर्तव्यनिष्ठा: जिलाधिकारी

संस्कार उजाला

गाजियाबाद (आशा चौधरी)
गाजियाबाद अध्यापक की जिम्मेदारी है निपुण छात्र व निपुण विद्यालय बनाना: इन्द्र विक्रम सिंह दुर्गावती देवी सभागार, विकास भवन में "निपुण कार्यशाला" का शुभारम्भ जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बैठक में उपस्थित गणमान्यों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया और कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके प्रति उत्साह और रूचि होना आवश्यक है। इसलिए सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए



अपने अन्दर उत्साह, जोश और रूचि लायें। जिससे आपके अन्दर बच्चों को भिन्न,भिन्न तरीकों से पढ़ाने के नये,नये तरीके सर्जन होंगे। तभी आप लोग समझ पायेंगे की कमजोर या देर से समझने वाला या ना समझ पाने वाले विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाये। जब आप समझ जायेंगे की किसी छात्र को किसी विधि से पढ़ाना है तो हर एक



छात्र निपुण छात्र व हर एक विद्यालय निपुण विद्यालय होगा। अतः छात्रों को देखे और समझे कि छात्र की रूचि किस प्रकार की है और तब आप उसे समझायेंगे तो वह जरूर समझेगा और तब आपका वह कमजोर विद्यार्थी निपुण विद्यार्थी बनेगा। आपके द्वारा विभिन्न तरीकों से छात्रों को निपुण बनाया जाना ही आपकी



कर्तव्यनिष्ठा है। अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वे अपने शिष्यों सहित विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने इससहयोगात्मक पर्यवेक्षण ढ़ को प्रभावशाली बनाने के लिए एआरपीएस द्वारा उचित फीडबैक और मार्गदर्शन देना आवश्यक है।



उन्होंने बताया कि जनपद में एआरपी, एसआरजी, बीईओएस ने मिलकर जनपद में सरांनीय काम किया है। उन्होंने एआरपीएस का प्रोत्साहन किया और निपुण के अंदर जिले की प्रगति को प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही साथ उन्होंने विभाग को एनएटी और एनएसएस परीक्षा से सम्बंधित तैयारियां और परिणाम पर ध्यान देने और सुचारु

रूप से परीक्षा कराने का निर्देश दिया। ओ. पी. यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रतिभागियों को ह्यमिशन मोडल पर हट निश्चय के साथ काम करने के लिए निर्देश दिया और प्रतिभागियों से आगामी एनएटी और एनएसएस परीक्षा के विषय में कुछ जानकारी साझा की। उन्होंने सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। कार्यशाला में मंच संचालन एसआरजी पूनम शर्मा, देवनकुर, जिला समन्वयक अरविंद कुमार, रूचि त्यागी, राकेश एवं डायट मेत्रर पिंटू द्वारा किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से डायट वरिष्ठ प्रवक्ता शाहीन, निपुण सेल की टीम, जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी, डायट मेत्रर एआरपी, एसआरजी, जिला समन्वयक मौजूद थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा भावी विधायक।



संस्कार उजाला

गाजियाबाद (आशा चौधरी)
एवं जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान के नेतृत्व में ADM गंभीर ,DIO योगेंद्र प्रताप की अगुवाई में भाजपा परिवार के साथ Opulent mall PVR cinemas में साबरमती फिल्म देखने पहुंचे। थे साबरमती फिल्म के दौरान रूबरू होने के लिए कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा एमएलसी दिनेश गोयल, महापौर

सुनील दयाल, महामंत्री सुशील गौतम मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी बालकृष्ण गुप्ता अशोक भारतीय महिमा गुप्ता भीम शर्मा पार्षद पप्पू नागर, ओम दत्त कौशिक, मनोज गिरी, प्रतीक माथुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण महानगर पदाधिकारी मोर्चे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष आदि प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदीप चौधरी महानगर मीडिया प्रभारी भाजपा।

हड़ताल में चैंबर खोलने वाले वकीलों और टाइपिस्टों पर एक्शन

गाजियाबाद। जिला जज कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बृहस्पतिवार को भी वकीलों का धरना जारी रहा। बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि शुकवार से सभी वकीलों अपना चैंबर बंद रखेंगे चैंबर खुला पाए जाने पर पांच हजार रुपये का जुमाना लगाया जाएगा। टाइपिस्ट बैठे मिलने पर दो हजार रुपये का जुमाना लगेगा। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 13 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई है। इसमें पूर्व बार अध्यक्ष और पूर्व बार सचिव शामिल हैं। बार एसोसिएशन ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बार सचिव अमित नेहरा के मुताबिक कचहरी में आने वाले अधिवक्ता अपने चैंबर की बजाय धरने पर बैठें। उसके लिए चैंबर पूरी तरह से बंद रखना अनिवार्य किया गया है। चैंबर खुला पाए जाने पर अधिवक्ता पर पांच हजार रुपये का जुमाना लगाया जाएगा। बार



एसोसिएशन द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं की सदस्यता निरस्त करने की कार्यवाई की जाएगी। कचहरी परिसर में में ठेले वाले, टाइपिस्ट और स्टॉप वेंडर भी काम नहीं करेंगे। ऐसा करते पाए जाने पर दो हजार रुपये का जुमाना लगाया जाएगा। बृहस्पतिवार को बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव लाल बहादुर सिंह, लोकेश कुमार शर्मा, विनोद कुमार वर्मा, संतोष जाटव, विजय गौड़, परविंदर नागर और विश्वास त्यागी धरना स्थल पर क्रमिक अनशन पर बैठे। आंदोलन की रणनीति तैयार करने की

जिम्मेदारी पूर्व अध्यक्ष राम अवतार गुप्ता, विजयपाल राठी, राकेश त्यागी काकड़ा, अनिल पंडित, मुनीश त्यागी, पूर्व सचिव अतुल शर्मा, विनोद वर्मा, नरेश चौधरी, सुंदर त्यागी, परविंदर नागर समेत वरिष्ठ अधिवक्ता और गजेब खान और जयवीर सिंह को सौंपी गई है। शनिवार को वकीलों की महापंचायत में कई जनपदों से आए बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी थी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक शर्मा के मुताबिक जिला जज पर कार्यवाई होने तक वकील उनकी कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे हड़ताल करने वालों की मांग है कि एक सप्ताह में न्यायाधीश का निर्णय, ट्रांसफर या बर्खास्तगी नहीं हुई तो हर बुधवार को पूरे प्रदेश में हड़ताल रहा करेगी। बता दें वकीलों का कहना है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही भी नहीं हुई है।

दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का कहर --डॉ बी पी त्यागी देंगे गरीब मरिजों को फ्री नाक, कान व गले का इलाज।

संस्कार उजाला

गाजियाबाद (आशा चौधरी)
एनसीआर में डॉ बी पी त्यागी का बड़ा बयान पॉल्यूशन को लेकर डॉ बी पी त्यागी ने कहा कि एनसीआर में पॉल्यूशन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड आपको बताते चलें पॉल्यूशन लेवल है वह अब 1600 के करीब है जो इंटरनेशनल मानिटर बता रहा है लेकिन जो भारत का मानिटर है वह 500 से ऊपर नहीं बता पाता है इसलिए बताया जा रहा है कि 500 है लिमिट लेकिन एकदम लिमिट जो है वह 1600 है और उसके पार है यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें पॉल्यूशन को जो एक कण होता है वह हमारे नाक के रास्ते से फेफड़े की झिल्ली से पार होते हुए खून में मिल जाता है और 2.5 एएमएम कण जो हमारी जितनी भी खून की नसे होती उन पर सूजन पैदा करता है उसके साथ कैल्शियम

वहां डिपॉजिट हो जाता है तो उसे ब्रेन अटैक हो सकता है उसे हार्ट अटैक हो सकता है उसे लिवर खराब हो सकता है गुर्दे खराब हो सकते हैं उसे किसी भी अंग का कैंसर हो सकता है जैसे स्केमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है और स्क्रॉन की सारी एलर्जी बालों की एलर्जी अस्थमा यह सब उससे होता है और अगर कोई अस्थमा का मरीज हो तो वह मल्टी ऑर्गन फैलियर में चला जाता है जो हमारी प्रेनेट बहने हैं उन बच्चों में कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं जैसे न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट होता है या हार्ट डिजीज होती है जो बूढ़े हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनको यह कण बहुत ही खतरनाक होता है उनकी जान ले सकता है जो हमारे बड़े पोथे हैं उनमें 18 गुना हार्मफुल इफेक्ट है उनकी पलियां पर एक सेटीमीटर के करीब धूल मिश्री जमा



हो चुकी है तो उनको जो अपनी नॉर्मल प्रक्रिया है फोटोसिंथिसिस कि वह नहीं हो पा रही है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा रही है और वह ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एनवायरमेंट में ऑक्सीजन जो पहले 21% थी वह अब 6% रह गई है इसलिए भी सांस में लोगों को दिक्कत आ रही है अब यह जो मुद्दा पराली वाला उठाया है इन लोगों ने एक्शन में पराली वाला मुद्दा नहीं है

दिल्ली के आसपास 16 के करीब कोयले के प्लांट है जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और वह इस लेवल तक पहुंच रहा है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क हमेशा एनसीआर में चलता रहता है उनको नहीं रोका जाता है और ग्रैप फॉर जो इन्होंने स्टार्ट किया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम इसके नहीं हटाएंगे तब तक लागू रहेगा इससे कुछ संभावना है कि शायद यहां के वातावरण में कुछ सुधार आए लेकिन तब तक के लिए डॉ बी पी त्यागी ने एडवाइजर सभी नागरिकों के लिए यह सलाह दी जाती है। कि सब मांस पहन के बाहर निकले मांस कपड़े का होना चाहिए लेयर होना चाहिए और गिला करके पहने तो बहुत अच्छा है एडेक्वेट पानी पीए अगर 60 किलो का आदमी है तो 3 लीटर कम से कम पानी पीए एक दिन में और हरी

सब्जियां खूब खाएं जो एंटीऑक्सिडेंट का काम करती है और अच्छा तो यह है, की बिना काम के बाहर न जाएं हो सके तो अंदर घर में रहे और अपने घर में भी एयर प्यूरीफायर लगाएं या ऐसे प्लांट लगाए जो हवा को साफ करते रहे लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं बाहर काम करते हैं ढेली पटरी वाले हैं उनको यह सलाह दी जाती है कि आप सूती कपड़े पहने अपने शरीर को पूरे को कवर करें और मास्क जरूर पहने अपने पास पानी की बोतल हमेशा रखें और अगर कोई भी परेशानी आती है तो मेडिकल एड ले उसमें कोई ऐसा ना सोचे कि मेडिकल एड नहीं मिलेगी मेडिकल एड मिल जाएगा अगर गवर्नमेंट में लेना चाहेंगे गवर्नमेंट में मिलेगी अगर नहीं लेना तो मिलती है गवर्नमेंट में तोहफे ईएनटी अस्पताल आ सकते हैं हम अपने अस्पताल में हर तरह की सुविधा देंगे।

राज कुमार गोयल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

राज कुमार गोयल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी में आई. ई. ई. द्वारा आयोजित एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड

संस्कार उजाला

गाजियाबाद (आशा चौधरी)
कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ए ई सी ई - 2024) पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 22-23 नवंबर 2024 को किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक डॉ आर के यादव एवं डॉ अमित सिंघल ने बताया कि इस संगोष्ठी के लिए 1035 शोध पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से संगोष्ठी में 265 शोध पत्रों को प्रस्तुत किया जाएगा। चयनित शोध पत्र आई. ई. ई. ई. एक्सप्लोर में प्रकाशित होंगे इस संगोष्ठी के लिए इंडोनेशिया, सऊदी अरब, फिलीपीन्स, उज्बेकिस्तान, टर्की, सिंगापुर, मलेशिया, तथा भारत के विभिन्न



क्षेत्रों से शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। इस दो दिवसीय संगोष्ठी में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से सम्मानित लोग व्याख्यान देंगे। संगोष्ठी में विभिन्न देशों की प्रतिष्ठित संस्थानों के आमंत्रित वक्त भी

अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यह महत्वपूर्ण संगोष्ठी शोधकर्ताओं को नए उभरते हुए क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल लोगों के साथ भविष्य की समस्याओं और उनके व्यावहारिक समाधान,

वैज्ञानिक परिणाम और विषयों पर चर्चा करने और मिलने के लिए उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम की प्रेस वार्ता में संस्थान के वाइस चैयरमैन अक्षय गोयल, ग्रुप एडवाइजर डॉ लक्ष्मण प्रसाद, एरजीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ डी के चौहान, डायरेक्टर डॉ बी सी शर्मा, डीन आई आई आई डॉ पुनीत चंद्र श्रीवास्तव, डीन एक्सीडेंटेशन डॉ रामेन्द्र सिंह, डीन स्टूडेंट वेलफेयर एच गर्ग, संयोजक डॉ आर के यादव (डीन एकेडमिक) एवं डॉ अमित सिंघल (एचओडी, सी एस ई), डॉ विपुल गोयल (हेड एच आर) मौजूद रहे।

डीसीपी से मिले लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जताई नाराजगी

ग्रेटर नोएडा। दादरी कोतवाली क्षेत्र के बिसाहडा कोल्ड स्टोरेज में सील मांस लैब रिपोर्ट में प्रतिबंधित पशु की पुष्टि के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुमराह को लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ग्रेटर नोएडा पहुंचकर ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान से मिले। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि दादरी में कोल्ड स्टोर में मांस मिलने के बाद पुलिस ने कार्यवाई के नाम पर खानापूर्ति की है। गोमांस की तस्करी में लखनऊ में बैठे दो बड़े अधिकारियों की सल्लिपता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोर में गोमांस की सप्लाई खाड़ी के देशों में नहीं बल्कि बड़े



स्तर पर एनसीआर में हो रही थी। उन्होंने प्रकरण को शाहीन बाग से भी जोड़ा। विधायक ने डीसीपी को सौंपी शिकायती पत्र उन्होंने कहा कि पता चला है कि शाहीनबाग से जुड़े कुछ लोग भी गोमांस की तस्करी में शामिल है, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्यवाई नहीं की। उन्होंने आरोपितों पर एनएसए की कार्यवाई कि संसुति किए जाने की भी मांग करते हुए डीसीपी को एक शिकायती पत्र भी सौंपा।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अनुमोदन के प्रार्थना पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर तक बढ़ाई: डा.अतुल जैन

संस्कार उजाला

गाजियाबाद (आशा चौधरी)
उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में और भारतवर्ष के कुछ अन्य राज्यों में 20 नवंबर 2024 को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स फाउंडेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉ.अतुल कुमार जैन ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि 20 नवंबर को चुनाव होने वाले जनपदों में संस्थान, बैंक इत्यादि को बंद एवं अवकाश की घोषणा की गई है इसलिए 20 नवंबर की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। उसी क्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अब अंतिम तिथि 23 नवंबर 2024 तक कर दी है जिसके लिए सभी संस्थानों की ओर से अध्यापकों और छात्रों की ओर से डॉ.अतुल कुमार जैन ने अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के अध्यक्ष और सदस्य सचिव का धन्यवाद ज्ञापित किया है।



प्रशासन के बुलडोजर को रोकने के लिए 500 ट्रैक्टर तैयार

मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के विरोध में किसान खड़खड़ी के जंगल में ठंड में धरने पर डटे हैं। धरने के 17 वे दिन किसानों के धरने को गांव कैलीके प्रधान पति विजेन्द्र और कबट्टा के प्रधान नरेश ने समर्थन पत्र सौंपा। अब तक दस प्रधानों का किसानों को समर्थन मिल चुका है। किसानों का दावा है कि प्रशासन अपनी रणनीति बना रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन के बुलडोजर को रोकने के लिए किसानों ने पांच सौ ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं। दावा



किया कि किसान अपनी जान दे देगे। लेकिन जमीन नहीं देगे। गांवों का मिल रहा समर्थन धरने को संबोधित करते हुए आयोजक मामचंद नागर ने कहा कि क्षेत्र के गांवों का लगतार समर्थन मिल रहा है। अब तक क्षेत्र के दस गांवों के प्रधान बिजौली, गोविंदपुरी,

बधौली, कैली, पांची, धीरखेड़ा, कबट्टा, छतरी, खड़खड़ी, अतराड़ा का समर्थन किसानों को मिल चुका है। अन्य प्रधान समर्थन देने के लिए तैयार हैकहा कि प्रशासन 300 हेक्टर जमीन छतरी खड़खड़ी और गोविंदपुरी की सस्ते दाम में लेने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रशासन अपनी रणनीति बना रहा है। वही, किसानों ने अपनी रणनीति बना रखी है। प्रशासन के बुलडोजर को रोकने के लिए किसानों ने पांच सौ ट्रैक्टरों की तैयारी कर रखी है। कहा कि आने वाले

समय में आसपास के किसानों की जमीन सस्ते दामों पर प्रशासन सरकार को गुमराह करके हड़पने की तैयारी कर रहा है। प्रेस प्रवक्ता कमल सिंह फौजी ने कहा कि प्रशासन को किसी भी कीमत पर किसान जमीन नहीं देगे। उन्होंने कहा कि धरती उनकी मां है। किसी भी कीमत पर वे उसे नहीं देगे। इस अवसर पर किसान नेता जगवीर सिंह, अशोक प्रधान, सत्येंद्र, दयाचंद कवित एडवोकेट, कर्मवीर पटवारी, राजकुमार, गोपीचंद, लीलू नागर, अर्जुन त्यागी, जयपाल, समेत आदि किसान थे।

1979 बैच का फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर पुलिस को गुमराह करने वाला बुजुर्ग और साथी गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में दिल्ली निवासी एक वृद्ध का फर्जीवाड़ा सामने आया है। उसने खुद को मणिपुर कैडर का 1979 बैच का रिटायर्ड IPS अधिकारी और एटलअ का सिक्वोरिटी सलाहकार बताकर न सिर्फ पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ट्रांस हिंडन से मुलाकात की और पुलिस अफसरों पर एक केस के सिलसिले में आरोपी ने पैरवी की। कहा मेरे बैचमेंट डीजीपी भी रहे हैं पुलिस के मुताबिक इस फर्जी आईपीएस अधिकारी ने कहा कि सीबीआई व आईबी के



हेड मेरे बैचमेंट भी रहे हैं। अलग-अलग राज्यों के पूर्व डीजीपी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों अपना दोस्त बताकर अफसरों को गुमराह किया। बाद में जब गाजियाबाद कमिश्नरेट के अफसरों को संदेह

हुआ तो पता चला कि इस नाम के कोई पूर्व आईपीएस नहीं रहे। फर्जीवाड़ा सामने आने पर DCP ट्रांस हिंडन के पीआरओ ने साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस फर्जी आईपीएस को तलाश रही DCP ट्रांस हिंडन के पीआरओ नीरज राठौर का कहना है कि 14 नवम्बर शाम 4:39 बजे मेरे सीयूजी नंबर पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना परिचय वर्ष 1979 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अनिल कटियाल के रूप में दिया।

यह भी कहा मणिपुर में डीजी रैंक पर रहा हूँ। वर्तमान में वह एमएचए में सिक्वोरिटी सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अनिल कटियाल ने इंदिरापुरम थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के केस के आरोपी विनोद कपूर की पैरवी करते हुए जांच अधिकारी प्रमोद हड्डा पर विवेचना में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए। यह भी बताया कि गाजियाबाद में पुलिस के उच्च अधिकारी इसे गाड़ी तक छोड़ने भी आए। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।